RNI No. DELMUL/2012/47011

09 सितंबर, 2026 बुधवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 160

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

भारत के खिलाफ मिली जीत ही पाक क्रिकेट की बदहाली का कारण बनी : मोहम्मद यूसुफ 07

संक्षिप्त वार्ता

जहरीली शराब से 50 लोगों की हुई मौत

भोपाल। बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव का दावा है कि पार्टी ने पिछले पांच महीनों में छह बार ज्ञापन देकर बंडा में अवैध और जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने दावा किया की जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत हुई है।

डॉ. यादव ने सागर में पत्रकारों को ज्ञापनों की प्रतियां दिखाते हुए कहा कि अप्रैल से ही प्रशासन को बंडा क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार की जानकारी दी जा रही थी। ज्ञापनों के जरिए चेतावनी दी गई थी कि यह शराब लोगों के जीवन के लिए खतरा बन रही है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। अब बंडा में हुई मौतों के बाद पार्टी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है, जबकि प्रशासन की ओर से 22 मौतों की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, जिससे मौतों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि, सपा के 50 मौतों के दावे और पोस्टमार्टम नहीं होने के आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

समाजवादी पार्टी ने मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सागर कलेक्टर, एसपी और बंडा एसडीएम समेत उन सभी अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, जिन तक अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें पहुंची थीं। सपा ने कहा कि यदि ज्ञापनों पर समय रहते कार्रवाई की जाती और अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

ब्रह्मपुत्र पर चीन के बांध: भारत की बढ़ती चिंताएं और संभावित खतरे

नई दिल्ली। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और उससे हुई तबाही ने फिर हिमालयी क्षेत्र में विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े जोखिमों को रेखांकित किया है।

इस परिदृश्य में, भारत की चिंता चीन द्वारा तिब्बत में यरलुंग त्सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, पर पनबिजली परियोजनाओं के विस्तार को लेकर बढ़ गई है। चीन ने ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों पर कई छोटी-बड़ी पनबिजली परियोजनाएं पूरी कर ली हैं या उन पर काम कर रहा है, जिसमें जंगमू, जिएक्सू, जाचा और डागु जैसी रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएं प्रमुख हैं।

हालांकि, भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास मेडोग इलाके में प्रस्तावित एक मेगा-बांध परियोजना है। लगभग 60,000 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में से एक होगी। इसकी लोकेशन खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि नदी अंततः इसी क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर अरुणाचल और फिर असम से होकर बहती है। हिमालयी क्षेत्र अपनी सक्रिय भूवैज्ञानिक संरचना के कारण भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसके बाद इस विशाल बांध पर किसी बड़े भूकंप या भूस्खलन का असर गंभीर हो सकता है, जिससे अचानक वॉटर बॉम्ब जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है। यदि किसी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी खराबी के कारण बांध टूटता है, तो भारी मात्रा में पानी तेजी से निचले इलाकों में तबाही मचा सकता है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्य, खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। एक और बड़ी चिंता चीन की उस क्षमता को लेकर है जिससे वह निचले इलाकों में बहने वाले पानी के समय और मात्रा को प्रभावित कर सकता है। बांध नदी के प्राकृतिक बहाव को बदल सकते हैं। मानसून के दौरान अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है, जबकि सूखे के समय पानी की कमी हो सकती है।

...नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं

ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वोत्तर में समुदायों, खेती और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए ये बदलाव दूरगामी परिणाम वाले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र हिमालय से भारी मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर गाद बहाकर लाती है, जो असम और बांग्लादेश में खेती की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े बांध इस गाद का एक बड़ा हिस्सा अपने जलाशयों में रोक सकते हैं। अगर निचले इलाकों तक पहुंचने वाली गाद की मात्रा कम हो जाती है, तब इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ेगा, बल्कि नदी का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और उसके आवास भी बदल सकते हैं, जिसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर मजदूरों से भरी बोलेरो को ट्रक ने मारी टक्कर; 6 की मौत

वेब वार्ता, गोंदिया। महाराष्ट्र के गोंदिया को मध्यप्रदेश के बालाघाट से जोड़ने वाले गोंदिया-बालाघाट राज्य महामार्ग पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नागरा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही मजदूरों से भरी बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन वर्षीय बच्चे समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की किरनापुर और लांजी तहसील के अलग-अलग गांवों से मजदूर परिवार सहित बोलेरो क्रमांक एमपी-15 टी 3495 से तेलंगाना के हैदराबाद जा रहे थे।

'नौजवान सुन लीजिए...' वडोदरा से पीएम मोदी ने जेन-जी को दिया खास संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने वड़ोदरा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 35 हजार करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही यात्री ट्रेन और चार मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया.

वड़ोदरा

पीएम मोदी ने खासतौर पर जेन-जी को संबोधित किया. बता दें कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 6 हजार युवाओं को बुलाया गया था. इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को फूफाजी कहकर निशाना भी बनाया.

पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि, बीते बारह सालों में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है. इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था. इन नौजवानों में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा. 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई काम करने के लिए, फिर 2014 तक फाइलें यहां से वहां होती रहीं.

विकसित भारत की यात्रा को गति देने आया हूं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन-जी से संवाद करते हुए कहा, आज मैं विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए यहां आया हूं. इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से स्वच्छता का कार्य किया उसने सीना चौड़ा कर दिया. हर परिवार पर स्वच्छता का गहरा असर पड़ा है. लाल किले से मैंने संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है जिसमें गति शक्ति भी अहम है.

पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि, बीते बारह सालों में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है. इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था. इन नौजवानों में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा. 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई काम करने के लिए, फिर 2014 तक फाइलें यहां से वहां होती रहीं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि फाइल अटकती, लटकती और भटकती थी. 2014 में वडोदरा गुजरात और देश के लोगों ने मुझे गुजरात से निकालकर दिल्ली भेज दिया. पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में.. जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए 7-8 वर्ष में एक किलोमीटर फ्रेंट कॉरिडोर पर काम पूरा नहीं हो पाया था, अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद तीन-चार पीढ़ी आती तो भी नहीं होता.

भारत मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई मामले में अमेरिका को छोड़ देगा पीछे

दो साल में दुनिया में दूसरे नंबर पर होंगे हम

नई दिल्ली। भारत में मेट्रो रेल का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो की लंबाई 1170 किलोमीटर है। अगले दो साल में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन सकता है।

सरकार का अनुमान है कि जिस रफ्तार से देश में मेट्रो रेल का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए अगले दो साल में भारत मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। ऐसा हुआ तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के मुताबिक, अमेरिका में इस समय करीब 1386 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है। वहीं भारत में इसकी लंबाई 1170 किलोमीटर हो चुकी है। इस हिसाब से दोनों देशों के बीच करीब 216 किलोमीटर का अंतर बचा है। भारत में जिस तेजी से नए मार्ग बनाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि ये अंतर अगले दो साल में खत्म हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मेट्रो रेल का विस्तार पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से हुआ है। साल 2014 में देश के केवल पांच शहरों में करीब 245 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क था.

इंदौर भी शामिल है

भारत का टारगेट अब सिर्फ बड़े महानगरों तक मेट्रो रेल नेटवर्क देने का नहीं है। देश के कई दूसरे शहरों में भी मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए रास्ते तैयार होने से भारत के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई और बढ़ेगी। मेट्रो रेल के बढ़ते नेटवर्क में मध्य प्रदेश का इंदौर भी शामिल है। यहां मेट्रो रेल सेवा के नए मार्ग का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इसके बाद इंदौर में मेट्रो रेल करीब 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हो गया है, जिसमें नए मार्ग में 16 स्टेशन शामिल हैं। भोपाल में चारों ओर मेट्रो का काम जारी है।

अब मेट्रो रेल का विस्तार 26 शहरों तक हो चुका है। करीब एक दशक में देश में मेट्रो रेल की पहुंच और लंबाई दोनों में बड़ा इजाफा हुआ है। मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में चीन अभी दुनिया में सबसे आगे है। चीन में करीब 8000 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है। इसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है।

अरावली परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तय करने के लिए गठित हाई-पावर कमेटी (एचपीसी) को बड़ा झटका दिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मांग को सिरे से खारिज किया है। सीजेआई ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसा लगता है कि कमेटी उनके 9 फरवरी, 2027 को होने वाले रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है।

2029 लोकसभा चुनाव: परिसीमन, युवा मतदाता और डिजिटल राजनीति की नई दिशा

नई दिल्ली। 2029 के लोकसभा चुनाव अभी भले ही 3 साल दूर हों, लेकिन देश की भावी राजनीतिक दिशा तय करने वाली चर्चाएं और रणनीतिक मंथन अभी से तेज हैं। राजनीतिक दल और रणनीतिकार भविष्य के चुनावी परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। इसमें परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संभावित संख्या में वृद्धि, महिला आरक्षण का कार्यान्वयन, जेन-जी युवा मतदाताओं की निर्णायक भूमिका और राजनीतिक संवाद की बदलती शैली प्रमुख हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन संभावित परिवर्तनों के मद्देनजर अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। आगामी आम चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर अटकलें जोरों पर हैं। राजनीतिक गलियारों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर करीब 850 तक करने और महिला आरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रस्तावों पर बहस चल रही है। सीटों की संख्या में यह संभावित विस्तार राज्यों के प्रतिनिधित्व और चुनावी समीकरणों को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है, जिससे यह आने वाले समय की राजनीति का एक केंद्रीय बिंदु बन गया है। सत्तारूढ़ एनडीए भी अपनी संसदीय स्थिति को और मजबूत करने तथा दो-तिहाई बहुमत के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्षेत्रीय समीकरणों और नए गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि, 2029 के चुनावी नतीजों को लेकर अभी किसी तरह का निश्चित अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

इन चुनावों में जेन-जी मतदाताओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। 1997 से 2012 के बीच जन्मे इस वर्ग की आबादी 2029 तक लगभग 38 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो भारत की कुल आबादी का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा होगा। यह एक ऐसी बड़ी शक्ति होगी जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, और इस पीढ़ी के वोट चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस नई पीढ़ी की प्राथमिकताएं पारंपरिक चुनावी मुद्दों से हटकर दिखाई दे रही हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक की समस्या का समाधान, कौशल विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और बेहतर जीवन-यापन के अवसर जैसे मुद्दे सर्वोपरि हैं। जेन-जी मतदाता केवल खोखली घोषणाओं के बजाय नीतियों के ठोस परिणाम और सरकारों की जवाबदेही पर अधिक जोर देगा।

युवा मतदाताओं के बदलते व्यवहार ने राजनीतिक दलों को अपनी संचार और प्रचार रणनीति में भी बदलाव लाने पर मजबूर किया है। अब लंबे-लंबे भाषणों और पारंपरिक रैलियों के साथ-साथ रील्स, शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया कैंपेन जैसे डिजिटल माध्यमों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। राजनीतिक दल युवाओं तक उनकी ही भाषा और उनकी पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट है कि 2029 का लोकसभा चुनाव केवल सीटों के बंटवारे और राजनीतिक गठबंधनों की पारंपरिक लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह युवाओं की आकांक्षाओं, डिजिटल राजनीति के उदय और नए सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों की भी कड़ी परीक्षा होगा।

यूपी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू

नई दिल्ली। आगामी वर्ष उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और अब चुनाव की तारीखों को लेकर भी तस्वीर स्पष्ट होती दिख रही है। जनगणना की तारीखों में किए गए समायोजन के बाद झ चार चुनावी राज्यों में इसे पहले कराने और मणिपुर में इसे टालने के फैसले के चलते झ यह लगभग तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2027 में मतदान संपन्न कराया जाएगा। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना और चुनाव दोनों में ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में जनगणना की तारीखें बदलने से एक बड़े प्रशासनिक टकराव को टाल दिया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी और चुनावी मशीनरी पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा।

इन पांचों राज्यों में विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथियां अलग-अलग हैं। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल सबसे पहले 13 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद गोवा में 14 मार्च 2027, पंजाब में 16 मार्च 2027 और उत्तराखंड में 28 मार्च 2027 को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। अंत में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को पूरा होगा। चूंकि मणिपुर का कार्यकाल सबसे पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग 13 मार्च से पहले ही सभी पांचों राज्यों में चुनाव संपन्न कराने की व्यापक तैयारी में जुट गया है, ताकि सभी राज्यों में समय पर नई सरकारों का गठन हो सके। उत्तर प्रदेश, जहां की विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है, वहां अगर फरवरी या मार्च में चुनाव होते हैं, तो यह कार्यकाल समाप्त होने से लगभग दो महीने पहले होगा। यह चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत आयोग कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले तक कभी भी चुनाव करा सकता है, ताकि नई सरकार के गठन के लिए पर्याप्त समय मिल सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्बाध चलती रहे।

... और समयबद्धता के महत्व को उजागर करते हैं

जनगणना की नई तारीखों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में जनगणना का काम 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। तीन राज्यों में सिस्टमैटिक इंवेस्टिगेशन ऑफ रेसिडेंस (एसआईआर) का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि बाकी दो राज्यों में यह अभी जारी है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या घटकर 13.4 करोड़, गोवा में 10.6 लाख और मणिपुर में 19.3 लाख रह गई है। पंजाब और उत्तराखंड की अंतिम वोटर लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी, जिससे चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा और राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति को धार दे सकेंगे। यह पूरे घटनाक्रम चुनावी वर्ष में प्रशासनिक समन्वय और समयबद्धता के महत्व को उजागर करते हैं।

संपादकीय

मौत की इमारतों की राजधानी

दिल्ली देश की राजधानी है अथवा मौत की इमारतों का महानगर है! यह इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में मालवीय नगर के एक अवैध, संकरे कथित होटल में अग्निकांड हुआ, जिसमें 22 जिंदगियां भस्म होकर राख बन गईं। कभी राजेन्द्र नगर में बारिश का पानी भर जाता है, उसमें करंट भी प्रवाहित होने लगता है, नतीजतन आधा दर्जन युवा छात्र अचानक लाश बन जाते हैं। वे आईएएस बनने का सपना लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मौत ने सब कुछ छीन लिया। कभी लक्ष्मीनगर में हादसा हुआ और फिर युवा जिंदगियों पर विराम लग गया। इसी जुलाई में ही रोहिणी में इमारत गिरी, साकेत और करोल बाग में हादसे हुए। मुस्तफाबाद में 11 मौतें इससे पहले हो चुकी थीं। ये हादसे, मौतें नहीं, बल्कि हत्याएं हैं, क्योंकि बचने के बंदोबस्त शून्य थे। और अब संभ्रांत कॉलोनी मोतीबाग के पास सत्य निकेतन में भी एक 5-मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। रविवार रात तक 5 मौतों की पुष्टि की जा चुकी थी। तीन छात्र अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मौतों की संख्या अधिक भी हो सकती है, क्योंकि 25-30 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। इन तमाम इमारतों में एक तथ्य साझा है कि सभी अवैध थीं। न अग्निशमन विभाग का एनओसी, न नगर निगम का एनओसी, स्वीकृत मंजिलों से अधिक मंजिलों का निर्माण और कई इमारतें तो सालों पुरानी थीं, जिनका रखरखाव भी नहीं किया गया था। सत्य निकेतन वाली इमारत भी 36 साल पुरानी बताई गई है। उस पर विभाग ने सील लगा दी थी, लेकिन फिर न जाने कैसे, वह सील भी खुल गई और यह हत्याकांड हो गया। इस इमारत की तीन मंजिलें अवैध थीं, क्योंकि उसे भूतल और पहली मंजिल बनाने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन भूतल के ऊपर भी चार मंजिलों का निर्माण कर लिया गया। दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व चेयरमैन और फायर ब्रिगेड के पूर्व निदेशक ने चौंका देने वाला खुलासा किया है कि दिल्ली में करीब 75 लाख इमारतें हैं। उनमें से करीब 1.75 लाख इमारतों के नक्शे पास हैं। शेष सभी इमारतें अवैध और अतिक्रमण की हैं।

देश की राजधानी में 1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। उनमें से 1511 को अधिकृत, नियमित करने के मद्देनजर पीएम-उदय योजना के तहत रखा गया है। एक पुख्ता वोट बैंक की तैयारी...लेकिन यह कितना भयावह यथार्थ है! यदि इन अवैध, अनधिकृत इलाकों में कोई इमारत भरभरा कर गिर पड़ती है, तो कल्पना कीजिए कि नुकसान कितना होगा? सरकार मुआवजा भी नहीं देगी। आखिर ये अनधिकृत कॉलोनियां कैसे उभर आईं? किसने इन्हें बनाया और सरकार में किन्होंने इनकी मदद की? ये इमारतें कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान बनी होंगी, लिहाजा कोई एक चेहरा या पार्टी खलनायक नहीं है। इस भ्रष्ट हम्माम में सभी नंगे हैं। बहरहाल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अप्रैल, 2025 के बाद से 241.51 एकड़ जमीन पुनः वापस ली है या प्रक्रिया में है। इसके अलावा, 235 एकड़ से अधिक जमीन पर जो अतिक्रमण, अवैध कब्जे थे, उन्हें मुक्त कराने का अभियान भी तय किया गया है। एक अनुमान है कि 70-75 फीसदी दिल्ली में अवैध या अतिक्रमण वाले कब्जे या निर्माण हैं। झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर चला कर तो गरीबों को बेघर किया जा सकता है, लेकिन राजधानी में जो अतिक्रमणकारी फॉर्म हाउस हैं, उन पर निर्णायक, मिट्टी-मलबा करने वाली कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो दिखावे के लिए कुछ आंशिक तोड़-फोड़ जरूर की गई है। बहरहाल सत्य निकेतन की जो इमारत गिरी है, उसमें डिब्बेनुमा कुछ कमरे बनाए गए थे, जिन्हें हॉस्टल का नाम दिया गया था। एक कमरे में, एक बिस्तर का किराया 15,000-18,000 रुपए माहवार वसूल रहे थे। संकरे रास्ते, संकरी-एकतरफा सीढ़ियां और आपातकालीन बंदोबस्त शून्य थे। ऐसी इमारत के बेसमेंट में, बरसात के मौसम में, भरे पानी की स्थिति में कुछ निर्माण-कार्य किया जा रहा था। ऐसे में नींव का एक पिलर खिसका और पूरी इमारत धड़ाम से धरती पर गिरी। इन कमरों में केरल, हरियाणा, उप्र और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के वे छात्र रहते थे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे।

दबाव में एफएसएसएआई : जन स्वास्थ्य की जीत

एफएसएसएआई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए और 15 फरवरी 2022 को भारतीय आबादी के बीच पैक्ड फूड के लिए अलग-अलग फ्रंट ऑफ पैक लेबल के बारे में उपभोक्ताओं की सोच पर एक स्टडी शुरू करवाई। दो हफ्ते पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई को हानिकारक पैक्ड फूड पर चेतावनी वाले लेबल लगाने में ढिलाई बरतने के लिए फटकार लगाई। यह फटकार ह्य3 एसह्ल और ह्यअवर हेल्थ सोसाइटीह्ल द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान लगाई गई थी, जिसमें ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैक्ड फूड पर पैकेट के सामने की तरफ (फ्रंट ऑफ पैक) चेतावनी वाले लेबल लगाना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट (एचएसएसएफ) वाले पैक्ड फूड के लिए चेतावनी वाले लेबल अनिवार्य करने में एजेंसी की हिचकिचाहट से यह सवाल उठता है कि क्या वह कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में काम कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो कोर्ट को इस मामले में खास निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट ने नागरिकों, खासकर बढ़ते बच्चों की सेहत को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सख्त चेतावनी वाले लेबल के कारण पारंपरिक भारतीय स्नैक्स (जैसे नमकीन) पर ज्यादा फैट या नमक की मात्रा की वजह से लाल चेतावनी का निशान लग सकता है। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी चिंताओं की वजह से सरकार को लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता बढ़ाने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि वे क्या खा-पी रहे हैं। मीडिया की कुछ रिपोर्टों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को एफएसएसएआई ने पैक्ड फूड और ड्रिंक्स पर पैकेट के सामने की तरफ चेतावनी वाले लेबल लगाने का प्रस्ताव रख दिया है। ज्यादा चीनी, फैट या नमक वाले आइटम के बारे में सख्त लेबल न होने को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बाद उसने अपना रुख बदला है। एफएसएसएआई का कोर्ट में एफओपीएल (पैकेट के सामने चेतावनी लेबल) के हिस्से के तौर पर चेतावनी वाले संकेतों पर सहमत होना यह दिखाता है कि नियामक संस्था सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और जागरूक नागरिकों के दबाव के आगे झुक गई है।

चेतावनी वाले संकेत क्यों हैं जरूरी : हमारे देश में सेहतमंद और पौष्टिक खाना बनाने और खाने की पुरानी परंपरा रही है। हमारी पारंपरिक खाने की थाली में आमतौर पर प्रोटीन, विटामिन, काबोर्हाइड्रेट और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का सही संतुलन होता है। इसलिए, हमारी डाइट हमेशा से संतुलित रही है। हालांकि, हाल के दिनों में प्रोसेस्ड फूड का सेवन तेजी से बढ़ा है और बाजार अब अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से भरा पड़ा है। अहम बात यह है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाए गए इन अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड ने बाजार का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया है। वैज्ञानिकों का साफ मानना है कि ये अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड कैंसर जैसी कई गैर-संचारी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा, कंपनियां ग्राहकों को लुभाने और बच्चों को अपने उत्पादों का आदी बनाने के लिए अत्यधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करती हैं। हमारे देश में डाइट में चीनी, सोडियम और सैचुरेटेड फैट की ज्यादा मात्रा के कारण कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी व लिवर की बीमारियां तेजी से आम होती जा रही हैं। लोगों में पोषण के बारे में जानकारी की कमी और फूड पैकेजिंग पर चेतावनी वाले लेबल न होने के कारण, लोग अनजाने में इन हानिकारक चीजों का सेवन कर रहे हैं। इससे इन बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, जिन्हें अक्सर लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां कहा जाता है। अगर ऐसे हानिकारक फूड उत्पादों पर चेतावनी वाले लेबल लगे हों जो यह बताएं कि उनमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है और वे सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो ग्राहक संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक हो जाएंगे और खाना खरीदते समय सही फैसला ले पाएंगे। जहां इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों की बिक्री कम हो सकती है, क्योंकि ग्राहक उनके अस्वास्थ्यकर उत्पादों को छोड़ देंगे, दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।

इसलिए ग्राहकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि वे जो पैक्ड फूड खा रहे हैं, वे उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरे देशों में, चाहे वहां चेतावनी वाले लेबल लगाना अनिवार्य हो या न हो, कंपनियों को ग्राहकों की जागरूकता और रेगुलेटरी संस्थाओं की सतर्कता और निष्पक्षता के कारण दबाव का सामना करना पड़ता है। जहां पहले एफएसएसएआई ने चेतावनी वाले लेबल लागू करने का विरोध किया, वहीं स्वतंत्र मीडिया की रिपोर्टों से पता चलता है कि यही कंपनियां दूसरे देशों में अपने उत्पादों के कम हानिकारक प्रकार बेचती हैं। उदाहरण के लिए, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भारत में बिकने वाली फैंटा (एक सॉफ्ट ड्रिंक) में दूसरी जगहों पर बिकने वाले उसी उत्पाद की तुलना में तीन गुना ज्यादा चीनी होती है। हाल ही में यह भी पता चला है कि इंग्लैंड में ज्यादा नमक होने के कारण नेस्ले की मैगी को रेड सिग्नल के साथ बेचा जाता है, जबकि वही उत्पाद भारत में बिना किसी ऐसी चेतावनी के बेचा जा रहा है। यह साफ है कि जानकारी की कमी के कारण भारत में बच्चे ऐसे ड्रिंक्स पीकर और ऐसे अन्य उत्पादों का सेवन कर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और एफएसएसएआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि वह नागरिकों और खासकर बच्चों की सेहत को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिसर्च से साफ पता चलता है कि देश और दुनिया भर में नुकसानदायक पैक्ड फूड के बढ़ते सेवन और गैर-संचारी रोगों के बढ़ने के बीच सीधा संबंध है। गैर-संचारी रोग, जिनमें कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी व दिल की बीमारियां शामिल हैं, पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल रहे हैं। आज भारत में हर चार में से एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है और कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों से बचने का एकमात्र तरीका नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट का बहुत ज्यादा सेवन न करना है। हालांकि, जब बड़ी और जानी-मानी कंपनियों के उत्पादों में ये नुकसानदायक चीजें ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद बिना किसी चेतावनी के बेचे जाते हैं, तो इन महामारियों को रोकने का रास्ता बंद हो जाता है।

हेल्थ स्टार रेटिंग की कवायद : साफ दिख रही सच्चाइयों के प्रति पूरी तरह बेपरवाह होकर, एफएसएसएआई ने चिंतित नागरिकों, वैज्ञानिक समुदाय और विशेषज्ञों की समझदारी भरी बातों को नजरअंदाज करना जारी रखा। अस्वास्थ्यकर भोजन, खासकर चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट से भरपूर भोजन पर चेतावनी के संकेत शुरू करने के बजाय एफएसएसएआई ने 4 अक्टूबर 2019 को ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ स्टार रेटिंग मॉडल की जांच शुरू की। एफएसएसएआई ने सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें खास तौर पर 1.5 स्टार एचएसआर सिस्टम और इसके न्यूट्रिशनल एल्गोरिदम के बारे में बताया गया। एफएसएसएआई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए और 15 फरवरी 2022 को भारतीय आबादी के बीच पैक्ड फूड के लिए अलग-अलग फ्रंट ऑफ पैक लेबल के बारे में उपभोक्ताओं की सोच पर एक स्टडी शुरू करवाई। अब जब एफएसएसएआई ने जन दबाव में न्यायालय में चेतावनी संकेत लागू करने को अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है, माना जा सकता है कि जन स्वास्थ्य पर सरकार जल्द ही सख्त रुख अपनाते हुए इसे जल्द लागू करेगी।

डा. अश्वनी महाजन, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

विदेशी निवेशकों का मूड बदला, शेयर बाजार से 7443 करोड़ की निकासी

शेयर बाजार बड़े-बड़े पूंजी निवेशकों की कमाई का अड्डा बन गया है। इसमें छोटे निवेशक और भारतीय संस्थागत वित्तीय निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार और सेबी जैसी संस्थाएं आंख बंद करके बैठी हुए हैं। विदेशी निवेशकों ने 7,443 करोड़ की निकासी की है। जो बाजार के लिए बड़े खतरे की घंटी है। पहले भी विदेशी निवेशक लाखों करोड़ों रुपए निकाल चुके हैं। पिछले दो महीने की खरीदारी से थोड़ी आशा बंधी थी, लेकिन सितंबर माह में अमेरिका-ईरान तनाव, महंगा कच्चा तेल, मजबूत डॉलर और बॉन्ड यील्ड ने विदेशी निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। भारतीय शेयर बाजार के विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशकों की निकासी से एक बार फिर शेयर बाजार में चिंता हो गई है। करीब दो महीने तक भारतीय बाजार में लगातार पैसा लगाने के बाद विदेशी निवेशकों ने सितंबर के पहले सप्ताह में ही 7,443 करोड़ रुपये की निकासी कर ली है। यह केवल आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं है, वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति विदेशी पूंजी की संवेदनशीलता का संकेत भी है। भारतीय शेयर बाजार से निवेशकों को मुनाफे की जगह घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका-ईरान तनाव ने कच्चे तेल, डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसका असर भारत जैसे बाजारों पर पड़ रहा है। यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेशकों का मूड पिछले दो महीनों में ही बदल गया है। चार महीने की लगातार बिकवाली के बाद जुलाई और अगस्त में एफपीआई ने भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा लगाया था। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में उन्होंने करीब 20,200 करोड़ रुपये और अगस्त में 30,919 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दो महीनों में कुल 51,119 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी भारतीय बाजार में आई। इसके तुरंत बाद सितंबर की शुरूआती बिकवाली ने बाजार के सामने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है। जो 4 माह पहले खड़ा हुआ था। विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय शेयर बाजार में बन नहीं पा रहा है।

भू-राजनीतिक तनाव का असर तथा कंपनियों में धोखाधड़ी की खबरों को लेकर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार को जोखिम के रूप में देख रहे हैं। शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव और निवेश अकेले भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करते हैं। वैश्विक ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमतें और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। तेल महंगा होने का सीधा असर आयात बिल, महंगाई और चालू खाते पर पड़ता है। इससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है। यह आशंका विदेशी निवेशकों को सतर्क कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है। मांग कम हो रही है। इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर दिखने लगा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से भारत में आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, घोटाले के बड़े-बड़े मामले सामने आ रहे हैं, इससे निवेशक भयभीत होकर शेयर बाजार से बाहर निकल रहे हैं। 2026 में शेयर बाजार से निकासी का यह आंकड़ा चिंताजनक है। सितंबर की शुरूआती बिकवाली ने वर्ष 2026 में विदेशी निवेशकों की कुल निकासी को 2.32 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह आंकड़ा 2025 में 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से अधिक है। बीच-बीच में विदेशी पूंजी की वापसी बाजार में भरोसे का संकेत देती है, उनका बार-बार तेजी से बाहर निकलना, भारतीय शेयर बाजार की विदेशी पूंजी पर निर्भरता को उजागर करता है। विदेशी निवेशक जब शेयर खरीदते हैं, बाजार में तेजी को बल मिलता है। भारी बिकवाली होने का असर कई रूप में देखने को मिल सकता है। छोटे और घरेलू निवेशकों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है।

शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था की असली परीक्षा आने वाले कुछ महीनों में सामने आएगी। विशेषज्ञों की नजर विदेशी निवेशकों के उस रुख पर है। यदि अमेरिकी बॉन्ड पर आकर्षक रिटर्न मिलता है। डॉलर मजबूत बना रहता है, ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी का बड़ा हिस्सा उभरते बाजारों से निकलकर विकसित बाजारों में निवेश की संभावना बढ़ेगी। जो भारतीय बाजार के लिए विदेशी पूंजी के उतार-चढ़ाव के बावजूद अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय अर्थ व्यवस्था की घरेलू मांग, कंपनियों की आय, सरकारी निवेश और घरेलू संस्थागत निवेशक, बाजार को सहारा दे सकते हैं। वैश्विक जोखिमों को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार में दोहरी मार पड़ रही है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय शेयर बाजार में नए इशू आ रहे हैं। इसमें मनमाना प्रीमियम लिया जा रहा है। विदेशी निवेशक इस खेल को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय शेयर बाजार में उनके लिए दीर्घकालीन निवेश करने के लिए कोई अवसर नहीं है। जिसके कारण विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। निवेश करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है।

लेखक- सनत जैन

श्रेष्ठ विश्व के निर्माण हेतु सशक्त मीडिया सेमिनार 9 सितंबर से आबुराज में!

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय विश्व शांति व सदभावना के लिए मीडिया को आध्यात्म से जोड़ने और पत्रकारों को राजयोग अभ्यास कराकर उन्हें तनावमुक्ति के गुर सीखाने के लिए 9 सितंबर से 13 सितंबर तक मीडिया सेमिनार का आयोजन राजस्थान के आबूराज के मानसरोवर परिसर में कर रहा है। यह सम्मेलन श्रेष्ठ विश्व के निर्माण हेतु सशक्त मीडिया विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस महासम्मेलन में 1500 से अधिक मीडिया कर्मियों के लेने की व्यवस्था की गई है।

इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक पत्रकारिता की ओर प्रेरित करना है साथ ही साथ पत्रकारों के मानसिक दबाव को राजयोग के अभ्यास के माध्यम से कम करना भी है। पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ ,कर्तव्यनिष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए ब्रह्माकुमारीज समय समय पर ऐसी सेमिनार करती रही है,ताकि मीडिया जगत में सच परोसने वालो की संख्या बढ़ सके।ब्रह्माकुमारीज मीडियाविंग के मुख्यालय समन्वयक बीके शांतनु भाई के संयोजन में देशभर से चुनिंदा पत्रकारो,मीडिया प्राध्यापको व संस्थान प्रमुखों के माध्यम से मीडिया व अध्यात्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर चिंतन के लिए यह मीडिया सेमिनार आयोजित की जा रही है।बीके शांतनु भाई ने बताया कि इस बार के मीडिया सेमिनार में जो विषय विभिन्न सत्रों में विमर्श हेतु रखे गए है उनमें सूचना से आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर, ध्यान एवं दैनिक जीवन मे आध्यात्मिक अनुपयोग, अंतर यात्रा: आत्म स्वरूप की खोज, सत्य, विश्वास व पारदर्शिता: मीडिया उत्तरदायित्व, आंतरिक स्थिरता हेतु राजयोग ध्यान की शक्ति का उपयोग, परमात्मा की अनुभूति, मीडिया में एआई : नवाचार व उत्तरदायित्व के मध्य सन्तुलन, उत्तरदायी सोशल मीडिया, शांति के नये युग की ओर सेतु के रूप में मीडिया तथा सफल जीवन हेतु कर्मदर्शन आदि शामिल है।

ब्रह्माकुमारीज मीडियाविंग के चेयरपर्सन बीके करुणा भाई का कहना है कि आज भी मीडिया अपनी सार्थक जिम्मेदारी निभाता आया है और विचलित हुए बिना राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकारों को आमजन के सामने लाने में मीडिया का हमेशा अहम योगदान है।इसीलिए ब्रह्माकुमारीज संस्थान पिछले 28 वर्षो से पत्रकारिता को आध्यात्मिकता से जोड़कर देश विदेश के पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षित कर रहा है।वर्तमान दौर में मीडिया के माध्यम से परोसे जा रहे सत्य की सारगर्भित विवेचना होने और देश की अर्थव्यवस्था, चुनाव, राजनीति व मीडिया की स्वतंत्रता को भी रेखांकित किया जाता है। मीडिया की विभिन्न चुनोतियो की ओर ध्यानाकर्षण कराने और मिडिया पर आए संकट को भी परिभाषित किया जाएगा।सच यह भी है कि देश मे सच लिखने वाले अच्छे पत्रकारों की संख्या भी कम नही है लेकिन अगर ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाओं के माध्यम से पत्रकारों को समय समय पर मिशनरी पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षण किया जाए तो अर्द्ध सत्य परोसने वालो की संख्या घट सकती है और सत्य आधारित मूल्यपरक पत्रकारों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है।ब्रह्माकुमारीज मीडियाविंग के नेशनल कोर्डिनेटर बीके निकुंज भाई युवा पत्रकारों के चरित्रनिर्माण पर जोर देते है ,उनका कहना है कि देश और समाज को उन्नत करने के लिए मूल्यो को समझना व उनपर चलना जरूरी है। मीडिया में अपेक्षित सुधार के लिए ब्रह्माकुमारीज के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल मीडिया सेमिनारों की आज के दौर में सबसे ज्यादा आवश्यता है।

तभी मीडिया अच्छे काम करके देश व समाज मे अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है।वास्तविकता यह भी है कि लोकतंत्र में मीडिया के महत्व को नकारा नही जा सकता और ब्रह्माकुमारीज के इस विषयक योगदान की सराहना होनी ही चाहिए।क्योंकि ब्रह्माकुमारीज के माध्यम से पत्रकारों को निरन्तर मूल्याधारित पत्रकारिता का प्रशिक्षण देकर हालात बदले जा सकते है।ब्रह्माकुमारीज मिडियविंग मुख्यालय समन्वयक बीके शांतनु मानते है कि पत्रकारों द्वारा की गई सामाजिक सेवा व सामाजिक मूल्यों को बचाये रखने के उनके योगदान को भुलाया नही जा सकता।साथ ही हमे अच्छी सोच पैदा करनी होगी ,तभी हम मीडिया को अच्छा बना सकते है।

मीडिया में आये दिन हो रहे बदलाव और उसके प्रभाव को लेकर भी इस सम्मेलन में चर्चा होगी।पत्रकारिता के क्षेत्र में नए विद्यार्थियों की अपेक्षाओं और इस दिशा में आमजनमानस की सोच को रेखांकित करते हुए बाजारवाद के बाद भी मूल्यों का बचा रहना ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है।मीडिया सम्मेलन में देशभर से भाग लेने वाले पत्रकार संकल्प लेते है कि वे ब्रह्माकुमारीज से जाकर अपनी लेखनी के माध्यम से सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देंगे,क्योंकि पत्रकारिता में आध्यात्म के समावेश से ही समृद्ध भारत की तस्वीर बनेगी। पत्रकार अपने समाचार के माध्यम से समाज में आशा जगाने वाली सकारात्मक खबरों को प्रस्तुत करने की पहल भी ब्रह्माकुमारीज से प्रेरित होकर करते है। इससे ही मीडिया समाज को मानसिक स्वास्थ्य परोस सकता है। समाज और जीवन को प्रभावित करने वाली जो भी गतिविधियां हमारे समाज में हैं, उसमें समाज को प्रभावित करने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है।देश को सही मायने में स्वर्णिम भारत बनाना है तो मीडिया को सच्चाई दिखाने के अपने दरवाजे खोलने होंगे । सन 1936 से स्थापित ब्रह्माकुमारीज में पचास हजार ब्रह्माकुमारी बहनें समर्पित रूप से अपनी रूहानी सेवाएं दे रही हैं,वही दुनियाभर में संस्था के 20 लाख विद्यार्थी नियमित राजयोग ध्यान करते हैं। जो अपने आप मे सुखद व विश्व शांति का कारक है।इस संस्थान की मीडिया सेमिनार में भाग लेकर व राजयोग का नियमित अभ्यास करके बड़ी संख्या में पत्रकारों के अंदर सकारात्मक बदलाव आए है।लेखक ब्रह्माकुमारीज मिडियाविंग के आजीवन सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार है)

लेखक-डॉ श्रीगोपाल नारसन

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

रक्षा समझौते की आड़ में पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य जमावड़ा

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लंबे समय से दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सैन्य तैयारियों का विस्तार लगातार जारी है। सऊदी अरब और तुर्किये के साथ हाल में हुए रक्षा सहयोग ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित दिखाई नहीं देती, बल्कि आधुनिक ड्रोन, मिसाइल तकनीक और लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यही वजह है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ इस नए सैन्य समीकरण को गंभीरता से देख रहे हैं।

अगस्त में पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य हवाई अड्डों पर तुर्किये के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही ने भी इन आशंकाओं को बढ़ाया है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ ही दिनों के भीतर तुर्किये के सी-130 और ए-400एम जैसे परिवहन विमानों ने पाकिस्तान के अलग-अलग एयरबेस का इस्तेमाल किया। इस गतिविधि को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि हथियारों की वास्तविक मात्रा और पूरी खेप के बारे में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक और उपकरणों का सहयोग कोई नई बात नहीं है।

तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। ड्रोन तकनीक से लेकर नौसैनिक परियोजनाओं और लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण तक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। पाकिस्तान को तुर्किये की बायरक्तार टीबी2 और अकिंसी जैसी ड्रोन प्रणालियों में रुचि है। इन प्लेटफॉर्मों की खासियत यह है कि इनका इस्तेमाल निगरानी के साथ-साथ सटीक हमलों के लिए भी किया जा सकता है। अकिंसी जैसे भारी ड्रोन अपेक्षाकृत अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम हैं और लंबी अवधि तक अभियान में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही तुर्किये की केमांकेश जैसी मानव रहित क्रूज मिसाइल तकनीक भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसी प्रणालियां आधुनिक युद्ध में पारंपरिक हथियारों से अलग भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन्हें लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले के लिए आधुनिक सेंसर तथा मार्गदर्शन तकनीक से जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस तरह की तकनीक हासिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में ड्रोन और मानवरहित प्रणालियां युद्ध की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी हैं।

तुर्किये का सहयोग केवल नए हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने और उनके एवियोनिक्स तथा हथियार प्रणालियों को आधुनिक बनाने में भी तुर्किये की भूमिका रही है। पुराने लड़ाकू विमानों की सेवा अवधि और परिचालन क्षमता बनाए रखना किसी भी वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से पाकिस्तान अपने मौजूदा सैन्य संसाधनों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ता दिखाई देता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता है। इस समझौते को तीनों देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य सहयोग को संस्थागत रूप देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यदि किसी एक साझेदार की सुरक्षा पर गंभीर संकट आता है तो अन्य देशों के समर्थन का प्रावधान इस समझौते को सामान्य रक्षा सहयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इसी कारण इसकी तुलना कई स्तरों पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से की जा रही है, हालांकि इसे सीधे नाटो का विकल्प मानना जल्दबाजी होगी।

इस गठजोड़ में तीनों देशों की अलग-अलग ताकतें हैं। सऊदी अरब के पास आर्थिक संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र में प्रभाव है। तुर्किये के पास मजबूत सैन्य ढांचा, रक्षा उद्योग और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का अनुभव है। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु क्षमता और मिसाइल प्रणालियों का व्यापक आधार है। यदि इन तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा होता है तो पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक इसका रणनीतिक प्रभाव पड़ सकता है।

पाकिस्तान की घरेलू आर्थिक स्थिति इस सैन्य विस्तार को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। देश कर्ज, महंगाई और राजकोषीय दबाव से जूझ रहा है। इसके बावजूद रक्षा बजट में वृद्धि हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का सैन्य खर्च 2025 में करीब 11.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि थी। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी इस्लामाबाद अपनी सुरक्षा और सैन्य क्षमता को प्राथमिकता दे रहा है।

पाकिस्तान के लिए सैन्य आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण भारत के साथ उसका लगातार बना हुआ रणनीतिक तनाव भी है। हालिया सैन्य घटनाक्रमों के बाद पाकिस्तान अपनी वायु रक्षा, ड्रोन क्षमता और सटीक हमले की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक युद्ध में बड़ी संख्या में पारंपरिक सैनिकों के बजाय निगरानी ड्रोन, स्वचालित प्रणालियां, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं। इसलिए पाकिस्तान का ध्यान इन क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ाने पर होना स्वाभाविक है।

लेकिन पाकिस्तान की चुनौती केवल बाहरी मोर्चे तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहा विद्रोह इस समय उसके लिए गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकट बना हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे हथियारबंद समूहों की गतिविधियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दबाव बनाया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। यहां सुरक्षा की चुनौती का सीधा संबंध पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संसाधनों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं से भी जुड़ जाता है। बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना पर लगातार दबाव है। पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए समस्या यह है कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस संकट का स्थायी समाधान आसान नहीं है। क्षेत्रीय असंतोष, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के बंटवारे और विकास से जुड़े सवाल भी लंबे समय से उठते रहे हैं। यदि इन मुद्दों का राजनीतिक समाधान नहीं खोजा गया तो सैन्य अभियानों के बावजूद अस्थिरता बनी रह सकती है। यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य क्षमता और उसकी आंतरिक कमजोरियां एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। एक तरफ देश अत्याधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसे अपने ही एक बड़े प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सैन्य संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। आर्थिक दबाव के बीच रक्षा खर्च बढ़ाना भी सरकार के लिए आसान फैसला नहीं है। तुर्किये के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी का एक दूसरा पहलू चीन से उसके पारंपरिक रक्षा संबंध भी हैं। पाकिस्तान अब एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय चीन, तुर्किये और अन्य साझेदारों से अलग-अलग सैन्य तकनीक हासिल करने की रणनीति अपना रहा है। इससे उसे विकल्प मिलते हैं और अपनी सैन्य जरूरतों के मुताबिक विभिन्न प्रणालियों को जोड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। दक्षिण एशिया के लिए इस बदलते समीकरण का अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारी अब केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लक्ष्य पहचान, लंबी दूरी की मिसाइलें और आधुनिक एवियोनिक्स जैसे क्षेत्र आने वाले समय में उसकी रणनीति के केंद्र में रह सकते हैं। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम निगरानी और तकनीकी तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

हालांकि किसी भी रक्षा समझौते को केवल हथियारों की खरीद के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे आर्थिक हित, क्षेत्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और बदलते वैश्विक गठजोड़ भी काम करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का उभरता त्रिकोण इसी व्यापक बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सहयोग केवल रक्षा खरीद और सैन्य अभ्यास तक सीमित रहता है या तीनों देशों के बीच साझा सैन्य रणनीति का रूप लेता है।

पाकिस्तान के लिए असली चुनौती आधुनिक हथियार हासिल करना भर नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने की आर्थिक क्षमता, प्रशिक्षण, रखरखाव और दीर्घकालिक सैन्य रणनीति तैयार करना भी है। हथियारों का जखीरा किसी देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। आर्थिक स्थिरता, मजबूत संस्थाएं, राजनीतिक सहमति और आंतरिक शांति भी उतनी ही जरूरी हैं। यदि पाकिस्तान इन मोर्चों पर कमजोर रहता है तो बढ़ता सैन्य खर्च उसकी ताकत बढ़ाने के बजाय आर्थिक बोझ को और भारी कर सकता है।

मक्का रक्षा समझौते और तुर्किये से बढ़ते सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान की रणनीतिक दिशा को जरूर बदलने का संकेत दिया है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान कितने ड्रोन या कितनी मिसाइलें हासिल करता है। बड़ा सवाल यह है कि वह इन सैन्य क्षमताओं को किस रणनीति के तहत इस्तेमाल करता है और क्या उसकी अर्थव्यवस्था इस बढ़ती रक्षा महत्वाकांक्षा का बोझ उठा पाएगी। दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए भी यही आने वाले समय की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होगी।

लेखक- कांतिलाल मांडोत
(एल 103 जलवन्त टाउनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो-99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

प्रदूषण रोकने के लिए ट्रायर धुलाई के बाद लैंडफिल से बाहर निकलेंगे वाहन

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बड़ा कदम उठाया है। अब गाजीपुर, ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट से कूड़ा डालकर बाहर निकलने वाली गाड़ियां पूरी तरह धुलने के बाद ही सड़क पर आ सकेंगी। इसके लिए तीनों साइटों पर स्वचालित व्हील वॉश सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लैंडफिल साइट पर कूड़ा डालने के दौरान वाहनों के टायरों में भारी गंदगी और कीचड़ जम जाता है। बिना धुले जब ये गाड़ियां बाहर निकलती हैं तो जिन रास्तों से गुजरती हैं, वहां टायरों से गंदगी फैलती रहती है। यह गंदगी सूखने के बाद हवा के साथ उड़कर धूल कणों के रूप में वायु प्रदूषण बढ़ाती है, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है।

केजरीवाल ने शिक्षा को बताया गरीबी से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षा और साक्षरता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि साक्षरता गरीबी के चक्र को तोड़ने, बेरोजगारी कम करने और बेहतर भविष्य के निर्माण का सबसे प्रभावी साधन है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने और सफलता हासिल करने की शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि देश के हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके।

बंगला साहिब में कड़ाह प्रसाद की पर्ची के लिए सेल्फ-सर्विस मशीन लगाई

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। गुरुद्वारा बंगला साहिब में आने वाली संगत की सुविधा के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ाह प्रसाद की पर्ची लेने के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ-सर्विस मशीन शुरू की है। इससे श्रद्धालुओं को पर्ची लेने के लिए लंबी कतार में लगने से राहत मिलेगी।

कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब में मशीन की शुरूआत हेड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह की ओर से अरदास के बाद की गई। इसमें उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से संगत आसानी से कड़ाह प्रसाद की पर्ची प्राप्त कर सकेगी।

सीसीटीवी फुटेज ने 14 साल बाद आरोपियों को इंसाफ दिलाया

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के 14 साल पुराने एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए भाटिया एसिड प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक हरिंदर भाटिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस लंबे कानूनी विवाद का रुख केवल एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से पूरी तरह पलट गया। इसी फुटेज ने इंसाफ दिलाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुकृति झा की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ईएसआईसी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने मई 2007 से अगस्त 2010 की अवधि के दौरान कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन रजिस्टर और खाता-बही जैसे वैधानिक दस्तावेज जांच के लिए अधिकारियों को नहीं दिखाए थे। 17, 23 और 30 मई 2012 को अधिकारियों ने कंपनी का दौरा किया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिलने का दावा किया गया।

दिल्ली विधानसभा, सरदार पटेल विद्यालय और कई सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली विधानसभा, सरदार पटेल विद्यालय और कई सरकारी संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू किया और प्रभावित जगहों पर बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी।

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

मंगलवार सुबह के समय धमकी मिलने के बाद, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग यूनिट और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें उन जगहों पर पहुंचीं और संबंधित इलाकों की घेराबंदी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा टीमों द्वारा तलाशी ली गई किसी भी जगह पर अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। परिसरों की अच्छी तरह से जांच की जा रही है और अधिकारी एहतियाती इंतजामों के तहत स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ईमेल और धमकी के स्रोत की आगे की जांच चल रही है।

यह ताजा धमकी दिल्ली विधानसभा को लेकर पहले से मौजूद सुरक्षा चिंताओं के बीच आई है, जिसे पहले भी इसी तरह की बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इससे पहले, 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली की कई जगहों पर बम की धमकियां मिली थीं, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली थी, जिसमें 15 अगस्त को दोपहर 2:11 बजे कोर्ट में कथित धमाके की चेतावनी दी गई थी। उसी ईमेल में 15 अगस्त को दोपहर 3:11 बजे दिल्ली की जिला अदालतों में भी धमाकों की धमकी दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा, पांच अन्य जगहों पर फोन कॉल के जरिए बम की धमकियां मिली थीं। इनमें जामनगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग, एमबी रोड साकेत ऑफिस, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 और दिल्ली कैंटोनमेंट में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ऑफिस शामिल थे।

दिल्ली के अलावा इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में भी धमकी भरा मेल मिल चुका है। 18 अगस्त को नागपुर में एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों को बम विस्फोट की धमकी मिली थी। हालांकि, जब तलाशी ली गई तो स्कूलों से कोई संदिग्ध या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।

घड़ौली वार्ड में अतिक्रमण व अवैध डेयरियों पर कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के घड़ौली वार्ड में उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने सोमवार को निरीक्षण किया। अम्मा ब्लॉक से शुरू निरीक्षण आशीर्वाद अपार्टमेंट, जीडी कॉलोनी ए-ब्लॉक क्षेत्र से होते हुए जीबीबी पॉइंट पर संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध डेयरियों और सड़कों पर घूम रही आवारा गायों की समस्या पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया। उप महापौर ने अधिकारियों को अतिक्रमण चिह्नित कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध डेयरियों से फैल रही गंदगी, दुर्गंध और गोबर के निस्तारण से नालियां प्रभावित होने पर लाइसेंसिंग व स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के आदेश दिए गए। आवारा पशुओं से यातायात प्रभावित होने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग को पशु पकड़ने के निर्देश दिए।

घायलों का हाल जानने एम्स पहुंचीं रेखा गुप्ता, हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन पीजी हादसे में जख्मी छात्रों के परिजनों से यहां एम्स में मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, गुप्ता ने परिजनों से छात्रों के स्वास्थ्य और उपचार की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि सरकार घायल छात्रों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और छात्रों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों से घायल छात्रों की स्थिति और उन्हें दिए जा रहे उपचार की विस्तृत जानकारी भी ली। सत्य निकेतन इलाके में छात्रों के पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के तौर पर इस्तेमाल की जा रही इमारत रविवार को दोपहर करीब 1:30 बजे मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई। मलबे से कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें से सात लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। सीएमओ के बयान के अनुसार, चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गंभीर रूप से घायल छात्रों के उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो लगातार उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है ।

द्वारका पुलिस की बड़ी कार्रवाई

महिला उत्पीड़न मामले में फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। द्वारका जिला पुलिस की एंटी-जेल बेल और भगोड़ा अपराधी सेल ने महिला के खिलाफ क्रूरता के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे घोषित अपराधी (पीओ) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

आरोपी की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई जो हरियाणा के झज्जर जिले के कालियावास गांव का निवासी है। उसे 10 जुलाई को डबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में भगोड़ा घोषित किया गया था। उसे घोषित अपराधी घोषित करने का आदेश दिल्ली के द्वारका कोर्ट, दक्षिण-पश्चिम जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (महिला न्यायालय) सुभी गुप्ता द्वारा पारित किया गया था।

पुलिस के अनुसार, द्वारका के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के निर्देश पर घोषित अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर हरीश कुमार कर रहे थे और इसमें हेड कांस्टेबल राहुल यादव और कुलवंत शामिल थे। यह अभियान एसीपी (ऑपरेशन) सुभाष मलिक की देखरेख में चलाया गया।

पुलिस ने बताया कि 23 अगस्त को टीम को विशिष्ट सूचना मिली थी कि अनिल कुमार, जो मुकदमे से बच रहा था, झज्जर के बिरोहर गांव और उसके आसपास मौजूद था। सूचना मिलने पर टीम गांव पहुंची और जाल बिछाया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कुमार के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इसी बीच, 29 अगस्त को दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने एक अनसुलझे हत्या मामले को सुलझाने का दावा किया था, जिसमें एक 64 वर्षीय व्यक्ति और उसके सहयोगी को एक 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जो आरोपियों में से एक का बेटा था।

आरोपियों की पहचान 64 वर्षीय तालुकदार अंसारी और 49 वर्षीय मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने एक सुनसान कंटेनर में ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

सत्य निकेतन हादसा: सीएम रेखा गुप्ता ने घायलों का हाल जाना, बोलीं- सरकार देगी हरसंभव मदद

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में घायल हुए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर इलाज की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और प्रभावित लोगों को हरसंभव आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

हादसे के घायलों से मुलाकात के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि घटनास्थल से घायल अवस्था में निकाले गए 12 लोगों में से सात की मौत हो गई। मृतकों में दो मजदूर और पांच छात्र शामिल हैं। हादसे में घायल एक मजदूर अभी एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। उसके पैर में गंभीर चोट आई है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि हादसे में घायल छात्रों में से दो की हालत ठीक है। उन्हें इलाज के बाद बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की संभावना है। वहीं, एक छात्र को गंभीर चोटें आने के कारण आईसीयू में रखा गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मुख्यमंत्री ने आईसीयू में भर्ती छात्र के माता-पिता से भी मुलाकात की और उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी प्रभावित परिवारों को भरोसा दिया है कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों और घायल मजदूर के परिवारों को आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मृत बच्चों के परिजन शव लेकर दिल्ली से अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं और सरकार ने उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य खतरनाक इमारत को आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस इमारत को गिराया जाएगा और इसे बुधवार तक ढहा दिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

परिवारों से सम्पर्क में है सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रभावित परिवारों के लगातार संपर्क में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी जरूरत के समय हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई भी आगे महत्वपूर्ण होगी।

सर्दियों में धूल रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगी 200 एंटी-स्मॉग गन

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। सर्दियों में दिल्ली की सड़कों पर उठने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करीब 200 ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इन गाड़ियों के जरिए प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के साथ सड़क और पेड़ों की धुलाई भी की जाएगी। अलग-अलग सड़क मंडलों में जरूरत के हिसाब से इनकी तैनाती की जाएगी।

योजना के तहत सेंट्रल और नई दिल्ली रोड डिवीजन में 10, एसआरडी में आठ, नॉर्थ-वेस्ट रोड डिवीजन-2 में 10 और नॉर्थ-वेस्ट रोड डिवीजन-1 में 19 गाड़ियां चलाने की तैयारी है। इनके अलावा दूसरे सड़क मंडलों में भी कम संख्या में एंटी-स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। इस तरह पूरी व्यवस्था में करीब 200 गाड़ियां शामिल होंगी।

लागू होगी पीजी नीति, जरूरी होगा ला-इसेंस, जोनवार किराया सीमा होगी तय

सत्यनिकेतन हादसे के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का फैसला किया है। जल्द इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। नीति के तहत पीजी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा।

मंगलवार को शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में पीजी और किराये के मकानों में रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान सूद ने कहा कि एक से दो महीने के भीतर इस नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। सूद ने प्रस्तावित पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक 2026 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में पीजी संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा समेत अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय पीजी पोर्टल की व्यवस्था होगी। पोर्टल पर छात्रों को पीजी का किराया, सुविधाएं और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति जैसी जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाएगी।

...चर्चा भी हो चुकी है

उन्होंने बताया कि सरकार पहले से पीजी नीति और न्यायमूर्ति गौबा समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर काम कर रही थी इसके अलावा विश्वविद्यालयों और नरेला समेत खाली पड़ी सरकारी इमारतों में छात्रावास बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रहीं हैं। बता दें कि इस विषय पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा भी हो चुकी है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल, बोले- लोगों को कर दिया बेबस

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि हादसे वाली जगह पर मोबाइल जैमर लगाए जाने के कारण लोगों के लिए मदद मांगना मुश्किल हो गया था।

उन्होंने कहा कि जब मलबे के नीचे दबे लोग अपने मोबाइल फोन से परिजनों या राहत एजेंसियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस समय मोबाइल सिग्नल बाधित होने से उनकी परेशानी और दहशत और बढ़ गई होगी। सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार से पूछा कि सत्य निकेतन में मोबाइल जैमर लगाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हादसे के बाद प्रशासन की पहली प्राथमिकता मोबाइल नेटवर्क को बंद करना थी। उनका कहना है कि बिल्डिंग हादसे जैसी आपदा की स्थिति में मलबे में फंसे लोग अक्सर मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी लोकेशन बताते हैं और मदद मांगते हैं। ऐसे में मोबाइल सिग्नल को बाधित करने का निर्णय कई सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि जैमर लगे होने के कारण स्थानीय लोग भी एंबुलेंस या अन्य सहायता के लिए फोन नहीं कर सके। वहीं, यदि मलबे के अंदर कोई व्यक्ति जीवित था और उसने अपने मोबाइल से किसी रिश्तेदार या परिचित को कॉल करने का प्रयास किया होगा तो नेटवर्क बाधित होने की वजह से वह संपर्क नहीं कर पाया होगा। भारद्वाज ने कहा कि यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद भयावह हो सकती है। आप नेता ने राहत और बचाव कार्य में कथित देरी को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि राजधानी दिल्ली के बीचोंबीच हुए इस हादसे में एनडीआरएफ की टीम को मौके तक पहुंचने में दो से ढाई या तीन घंटे क्यों लगे। उन्होंने सरकारी

एंबुलेंस के भी करीब दो घंटे की देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। भारद्वाज के मुताबिक, हादसे के बाद सबसे पहले ब्लिंकिट की एक निजी एंबुलेंस मौके पर पहुंची, जबकि सरकारी एंबुलेंस बाद में पहुंची।

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राहत और बचाव का काम भी करीब दो से ढाई घंटे की देरी से शुरू हुआ और एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग तीन घंटे लग गए। उन्होंने कहा कि यह हादसा देश की राजधानी के बेहद महत्वपूर्ण इलाके में हुआ, जो लुटियंस दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है और प्रधानमंत्री आवास से करीब चार किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने हादसे के बाद मलबा हटाने में लगे समय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 100 गज की एक छोटी सी बिल्डिंग का मलबा हटाने में 24 घंटे से अधिक समय लगना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर राहत एवं बचाव कार्य में इतनी देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि घटनास्थल पर मोबाइल जैमर लगाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था और किस अधिकारी या विभाग ने इसके आदेश दिए थे।

उनका कहना है कि हादसे के दौरान राहत कार्य में तेजी लाने के बजाय संचार व्यवस्था बाधित करना गंभीर विषय है। भारद्वाज ने कहा कि सत्य निकेतन हादसे की घटनाओं को केवल एक स्थानीय हादसे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इससे राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविक स्थिति सामने आती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि राहत दल और एंबुलेंस समय पर क्यों नहीं पहुंचीं और मोबाइल नेटवर्क को बाधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

आप नेता ने केंद्र और दिल्ली सरकार की विकास संबंधी दावों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राजधानी में एक हादसे के दौरान राहत और बचाव व्यवस्था में इतनी देरी हो तथा लोगों के संपर्क के साधन तक बाधित हो जाएं, तो 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने और 7.8 प्रतिशत जीडीपी जैसी बातों का जमीनी वास्तविकता से कोई मेल नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़े दावों के बजाय जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

यूजीसी नेट री-एग्जाम: दिल्ली के उम्मीदवारों को सलाह, 9-10 सितंबर को ट्रैफिक पाबंदियों को देखकर निकलें

नई दिल्ली, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली में यूजीसी नेट जून 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें क्योंकि 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में यात्रा प्रतिबंधों की संभावना है, जिससे सड़क यात्रा लंबी हो सकती है और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में देरी हो सकती है।

परीक्षार्थियों के लिए जारी एक सलाह में परीक्षा देने वाली एजेंसी ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने यात्रा मार्गों की पहले से जांच कर लें, समय से पहले निकलें और निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के दौरान संभावित यातायात प्रतिबंधों, मार्गों में बदलाव या देरी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरिक्त समय अपने पास रखें। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

एनटीए ने कहा कि उम्मीदवारों को पहले से ही उचित व्यवस्था करनी चाहिए और यात्रा के समय में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे रिपोर्टिंग समय से काफी पहले अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें और अंतिम समय की किसी भी कठिनाई से बच सकें। अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की पुनर्परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार, पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी।

सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश स्तर के सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति, पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु यूजीसी-एनईटी परीक्षा आयोजित की जाती है। यूजीसी-नेट 2026 परीक्षा इस वर्ष जून में 87 विषयों में आयोजित की गई थी। हालांकि, उत्तर कुंजी जारी करने में देरी के लिए एनटीए की आलोचना की गई थी। अनंतिम उत्तर कुंजी रविवार को जारी की गई। इसके बाद, एनटीए ने कहा कि उसे अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के विषयों में कई त्रुटियों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं।

पुनर्परीक्षा आयोजित करने का लिया निर्णय

अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षाएं 9 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। अंग्रेजी की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट में होगी, जबकि वाणिज्य की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट में होगी। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इन तीन विषयों में से किसी एक का चयन किया था, वे आने वाले दिनों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होने वाली पुनर्परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियों के संबंध में राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान (एनटीए) को अनेक शिकायतें प्राप्त होने के बाद पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

निर्धारित समय पर घोषित किये जायेंगे परिणाम

इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और समिति की सिफारिश के अनुसार, एनटीए ह्लनिष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करनेह्व के लिए इन विषयों में परीक्षाएं फिर से आयोजित करेगा, अधिकारियों ने बताया। परीक्षा एजेंसी ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और सीटों का आवंटन कम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य 84 विषयों के परिणाम निर्धारित समय पर घोषित किए जाएंगे।

संक्षिप्त वार्ता

सण्डीला में राशनकार्ड संबंधी जनता दिवस, 141 आवेदन आए

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक। हरदोई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सण्डीला के आदेशानुपालन में मंगलवार को तहसील सण्डीला कार्यालय में खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित जनता दिवस का आयोजन किया गया। प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित जनता दिवस में आमजन की राशनकार्ड एवं खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित समस्याओं को सुना गया तथा उनके समाधान के लिए आवेदन प्राप्त किए गए।

जनता दिवस में विकास खंड सण्डीला, बेहन्दर, कोथावां, भरावन एवं कछौना सहित नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्ड से संबंधित कुल 141 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 53 आवेदन पत्रों का नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर ही तत्काल निस्तारण कर दिया गया। वहीं शेष 88 आवेदन पत्रों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों ने बताया कि इन आवेदनों का निस्तारण यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।

13 सितंबर को हरदोई में सुभासपा की महारैली, प्रदेशभर से जुटेंगे कार्यकर्ता

हरदोई, 8 सितंबर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की ओर से सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने के उद्देश्य से आगामी 13 सितंबर 2026 को हरदोई के नॉर्मल स्कूल ग्राउंड में विशाल सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल होंगे।

महारैली की तैयारियों और उद्देश्यों को लेकर मंगलवार को हरदोई गेस्ट हाउस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह महारैली केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने का व्यापक अभियान है। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती आपसी भाईचारे, समान अवसर और सामाजिक न्याय से होती है। प्रदेश के विकास में किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पिछड़े, वंचित और कमजोर वर्गों को सम्मान, अधिकार तथा विकास के समान अवसर मिलना जरूरी है।

जागेश्वर पाल प्रकरण में पीड़ित परिवार से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल

हरदोई। जागेश्वर पाल के साथ हुई घटना के बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। सपा नेताओं ने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को उचित मंच तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि समाज के कमजोर, वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होने पर उसके पक्ष में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है।

यूपी में अधर में लटकी पत्रकारों की पेंशन

मुरादाबाद/अमरोहा, 8 सितंबर। सत्ता से निकटतम संबंध और पारिवारिक नजदीकी को सार्वजनिक जवाबदेही के आड़े न आने देने वाले महान संसदीय योद्धा एवं पत्रकार हितैषी फिरोज जहांगीर गांधी की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकारों द्वारा उनकी निर्भीक विरासत को याद किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों को जन-जवाबदेही का आईना भी दिखाया गया। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सचिव डॉ. संतोष गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के पदाधिकारी महिपाल सिंह ने उनकी निर्भीक पत्रकारिता और निष्पक्ष संसदीय परंपरा को नमन करते हुए कहा कि आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तथा सभी सांसदों व विधायकों को फिरोज जहांगीर गांधी के सिद्धांतों से सबक लेने की जरूरत है।

अतिवृष्टि ने बुंदेलखंड के किसान की मेहनत पर फिर फेरा पानी

खेतों में डूबी उम्मीदें, उड़द-मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की फसलें बर्बाद

ललितपुर। बुंदेलखंड का किसान पहले से ही मौसम की मार और खेती की बढ़ती लागत के बीच किसी तरह अपनी फसल तैयार करने में जुटा था, लेकिन हाल के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि ने उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया।

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर जिले के बिरधा विकासखंड समेत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भर जाने से खरीफ की खड़ी फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। कई खेतों में फसलें जलमग्न हैं तो कहीं पानी में सड़ने लगी हैं। इससे किसानों के सामने फसल बचाने के साथ ही लागत वापस निकालने का संकट खड़ा हो गया है।

ग्राम मैनवार समेत आसपास के गांवों के पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर फसल क्षति का तत्काल सर्वे कराने और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बिरधा क्षेत्र में मुख्य रूप से उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की खेती होती है। लगातार हुई भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो गया, जिसके कारण तैयार होने की स्थिति में पहुंच चुकी खरीफ की फसलें पानी में डूब गईं।

राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी से संयुक्त सर्वे की मांग

पीड़ित किसानों ने मांग की है कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर प्रभावित गांवों में मौके पर भेजी जाए। टीम द्वारा प्रत्येक खेत का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक फसल क्षति का निष्पक्ष आकलन कराया जाए, ताकि नुकसान के अनुरूप किसानों को राहत मिल सके। किसानों ने अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति की रिपोर्ट शासन को भेजने तथा राज्य आपदा मोचक निधि से तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही फसल बीमा कराने वाले किसानों को बीमा नियमों के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने की भी मांग उठाई गई है।

कहीं पूरी फसल बर्बाद, कहीं खेतों में सड़ रही उपज

किसानों के मुताबिक कई खेतों में स्थिति इतनी खराब है कि फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। प्रभावित किसानों ने 80 से 100 प्रतिशत तक फसल नुकसान का दावा किया है। उनका कहना है कि बीज, खाद, दवा, जुताई और सिंचाई समेत खेती में लगाई गई पूरी लागत अब डूबने की स्थिति में है। फसल हाथ से निकलने के बाद किसानों के सामने परिवार की जरूरतें पूरी करने और अगली फसल की तैयारी के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बुंदेलखंड में खेती पहले से ही मौसम की अनिश्चितता पर निर्भर रहती है। कभी कम बारिश तो कभी सूखा और अब जरूरत से ज्यादा बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि ने इस बार उनकी उम्मीदों को भी पानी में बहा दिया है।

80 से 100 फीसदी नुकसान का दावा

राहत में देरी बढ़ाएगी किसानों की परेशानी

किसानों का कहना है कि खरीफ की फसलें उनके परिवार की आय का महत्वपूर्ण आधार हैं। फसल बर्बाद होने का मतलब केवल खेत में खड़ी उपज का नुकसान नहीं, बल्कि महीनों की मेहनत और खेती में लगाई गई पूंजी का डूबना भी है। ऐसे में यदि समय रहते सर्वे और क्षति का आकलन नहीं हुआ तो प्रभावित किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है।

किसानों को कुछ राहत मिल सके

किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि कागजी कार्रवाई में समय गंवाने के बजाय प्रभावित खेतों का तत्काल मौके पर सर्वे कराया जाए और पात्र किसानों को आपदा राहत तथा फसल बीमा का लाभ जल्द उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों को कुछ राहत मिल सके।

शेयर मार्केट के नाम पर साइबर ठगी गिरोह का पदार्फाश

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

फर्जी ऐप-वेबसाइट से ठगी, मास्टरमाइंड समेत 13 गिरफ्तार

ललितपुर। शेयर मार्केट में निवेश पर कई गुना मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का ललितपुर पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने फर्जी 'Nokia Securities' ऐप और वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार गिरोह लोगों को फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर उसमें निवेश की रकम और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाता था। जब पीड़ित रकम निकालने का प्रयास करते तो टैक्स, शुल्क और अन्य चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे जमा कराए जाते थे। एक पीड़ित की करीब 70 हजार रुपये की शिकायत से शुरू हुई जांच में पुलिस को बड़े नेटवर्क का पता चला। जांच में इसी गिरोह द्वारा वर्ष 2025 में एक व्यक्ति से करीब 11 लाख रुपये की ठगी किए जाने की जानकारी भी सामने आई।

6,357 संभावित पीड़ितों का डेटा बरामद

पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 6,357 संभावित पीड़ितों का डेटा और लगभग 600 म्यूल बैंक खातों से जुड़े सुराग मिले हैं। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को इधर-उधर किए जाने की आशंका है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7 आईफोन, 16 एंड्रॉयड मोबाइल, 15 कीपैड मोबाइल, 18 कंप्यूटर, एक एप्पल लैपटॉप, दो जियो वाईफाई राउटर, ब्रेजा और थार कार बरामद की गई हैं।

पुलिस के मुताबिक गिरोह में आरोपियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। कुछ फर्जी ऐप और वेबसाइट चलाते थे, जबकि अन्य लोग ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें निवेश के लिए तैयार करते और बैंक खातों व फर्जी सिम के जरिए रकम का प्रबंधन करते थे। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की कुल रकम का पता लगाने में जुटी है।

फरार शातिर अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

वेब वार्ता,कानपुर। पुलिस महानिदेशक रेलवे शप्रकाश डी० द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में रेल में हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त।

21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल में मा न्यायालय एडीजे 16 जनपद कानपुर नगर से प्राप्त एनबीडब्लू/82,83 सीआरपीसी में वारंटी अभि० समीर (26)पुत्र सिकन्दर नि० कश्यान बायापार सोई थाना बलरामपुर जिला कटिहार बिहार को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा

इलेक्ट्रानिक तथा सूचना के आधार पर काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था।

अभियुक्त को पकड़ने वाली टीम में मुख्य रूप से जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह, एसआई, शिव बाबू यादव, उ0नि0 अभिषेक शुक्ला थाना जीआरपी, हे0का0 शिव सिंह, वैश खान, का0 दीपक यादव, अश्वनी मौर्य थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल रहे।

राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजी गईं शिक्षिका विजयावती, डीएम ने किया सम्मानित

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 08 सितम्बर। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कम्पोजिट विद्यालय मंसूर नगर, पिहानी में कार्यरत शिक्षिका सुश्री विजयावती को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मंगलवार को जिलाधिकारी ने डीएम कार्यालय में शिक्षिका का स्वागत एवं सम्मान किया। जिलाधिकारी ने सुश्री विजयावती को पुरस्कार मिलने पर बधाई देते हुए उनके शैक्षिक समर्पण,

नवाचारपूर्ण कार्यों तथा विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समर्पण और शिक्षा में किए जा रहे नवाचार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षिका विजयावती की यह उपलब्धि उनके व्यक्तिगत प्रयासों और कर्तव्य के प्रति समर्पण का सम्मान होने के साथ ही जनपद के बेसिक शिक्षा परिवार के लिए भी गौरव का विषय है। उनका यह सम्मान अन्य शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचारपूर्ण शिक्षण के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी पिहानी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजनाः हरदोई में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, मशीनों पर मिलेगी 50% छूट

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हरदोई द्वारा विकास खण्ड भरखनी की ग्राम पंचायत मैकपुर में 'मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना' के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम प्रधान कु० रेनू देवी द्वारा किया गया।

उद्घाटन के अवसर पर ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को पापड़, अचार, कचरी, मसाला, आटा चक्की, पास्ता, दलिया और सेवई जैसे लघु उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में योजना की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों ने बताया कि 50% तक का अनुदानः प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए आवश्यक मशीन और उपकरणों की लागत पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

विशेषज्ञ मार्गदर्शन

फूड इंस्पेक्टर अजीत सिंह और कृषि वैज्ञानिक भूपेन्द्र यादव ने ग्रामीणों को प्रसंस्करण तकनीकों और खाद्य सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिवप्रकाश सिंह, कुमकुम सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बहू बेटी सम्मेलन में महिलाओं को किया जागरूक

वेब वार्ता, कमर खान

गैसड़ी / बलरामपुर। मिशन शक्ति के पंचम चरण के शुभारंभ के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह जनपद बलरामपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप मल्ल के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी राजकुमार पाण्डेय के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम महिला आरक्षी प्रभा सिंह, महिला आरक्षी सोनम, महिला आरक्षी प्रतिभा के द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.2 के तहत ग्राम लठावर डिहवा थाना को० गैसड़ी जनपद बलरामपुर में बहू बेटी सम्मेलन में महिलाओं ,बालिकाओं को दहेज, बाल विवाह न करने के लिए जागरूक किया गया तथा बाल विवाह कानूनी अपराध है इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा दहेज प्रतिषेध

अधिनियम के बारे में बताया गया तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ,वृद्धा पेंशन योजना ,विधवा पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई व पंपलेट वितरित किए गए।

सभी को वूमेन पावर लाइन 1090 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 यूपी आपातकालीन 112 एबुलेंस सेवा 102/108 महिला हेल्पलाइन 181 व साइबर हेल्पलाइन नं० 1930/ सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इत्यादि के बारे में बताया गया ' महिलाओ को थाने पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र एवं परिवार परामर्श केंद्र के बारे में बताते हुए सुगम कानूनी सहायता व शिक्षा के प्रति जागरुक किया गया ' बहू, बेटी, सास, आदि को परिवार में आपसी सामंजस्य बनाकर रहने व घरेलू विषयों पर चर्चा कर सभी को जागरूक किया गया. एकत्रित सभी महिलाओ द्वारा अपना अपना व पक्ष अपनी राय भी रखी गई' सभी उपस्थित महिलाओं से समस्या के विषय में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी को कोई समस्या नहीं है।

पेड़ काटने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गाँव में तनाव के बाद पुलिस तैनात

वेबवार्ता, हरदोई। कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के हूँसेपुर गांव में यूकेलिप्टस का सूखा पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में दबंगों की लाठी-डंडों से पिटाई का शिकार हुए सुशील (35) की मौत हो गई। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। एहतियात के तौर पर गांव में पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक की पत्नी सुशीला के अनुसार, 5 सितंबर की रात सुशील खेत पर जा रहे थे, तभी गांव के सम्मोहन, मीरा और करन ने उन्हें रोककर पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडों से पीट दिया।

देवरिया जिले में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के औचक निरीक्षण

डीएम ने पढ़ाया गणित और अंग्रेजी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

वेब वार्ता, देवरिया 08 सितंबर । देवरिया जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज प्रातः लगभग 8:30 बजे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बरहज का औचक निरीक्षण कर पठन-पाठन, आवासीय व्यवस्थाओं सहित अन्य आवश्यक सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से गणित व अंग्रेजी के प्रश्न भी हल कराए तथा स्वयं उन्हें पढ़ाया भी। पठन-पाठन से वे काफी संतुष्ट दिखे। यहां सभी अध्यापक उपस्थित रहे। साथ ही निरीक्षण के समय आवासित लगभग 92 छात्राएं भी उपस्थित रहीं।

जिलाधिकारी ने हॉस्टल पोर्टल एवं क्लास में सभी जगह छात्राओं की उपस्थिति को भी चेक किया। जिलाधिकारी ने किचन में बने भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। वे स्वयं चावल को चखकर गुणवत्ता की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने इस दौरान उपस्थित वार्डन व शिक्षिकाओं को निर्देश दिया कि पठन-पाठन की गुणवत्ता बेहतर रखें। उपलब्ध संसाधनों को पूरी पारदर्शिता के साथ छात्राओं तक पहुंचाएं। शिक्षा का बेहतर माहौल रखें, ताकि आवासित बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन के सापेक्ष छात्राओं की उपस्थिति भी हर हाल में दर्ज होनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता के साथ-साथ बच्चों सहित अभिभावकों को भी नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान एक-एक कक्षा का भी निरीक्षण कर पढ़ाई की जानकारी ली। कक्षा 6, 7 एवं 8 तीनों कक्षाओं में उन्होंने अंग्रेजी व गणित भी पढ़ाया। पठन-पाठन से वे काफी संतुष्ट रहे और आगे भी इसी तरह बेहतर माहौल बनाए रखने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के निर्देश संबंधित वार्डन व शिक्षिकाओं को दिए।

देवरिया में गो आश्रय केन्द्र से तीन दिनों में 13 बछड़ों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने बैठाया जांच

देवरिया 8 सितम्बर। देवरिया जिले के जिला पंचायत द्वारा लार विकास खंड में भागलपुर-सलेमपुर मार्ग पर कुंडौली चौराहे पर संचालित गो आश्रय केन्द्र में पिछले तीन दिनों में 13 बछडो.की मौत को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच टीम भेजा।

जिला प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को जिला प्रशासन ने जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षक रामनाथ यादव, बाबू जुबेर अहमद को मौके पर भेजकर जांच कराया गया ।इन जांच कर्मियों को कहना था कि केयर टेकर अशोक और उसकी पत्नी यहां कार्यरत हैं। दूसरे राजस्व निरीक्षक पारसनाथ दुबे को केयरटेकर सूचना देकर कहीं चला गया। एक सप्ताह से चारा-पानी के अभाव में 13 बछड़ों की मौत हो गई।

प्रवक्ता के अनुसार भागलपुर - सलेमपुर मार्ग पर कुंडौली चौराहे पर जिला पंचायत की तरफ से संचालित गो आश्रय केंद्र में तीन दिन में भूख से तड़पकर 13 बछड़ों की मौत हो गई है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिले के आला अफसरों से शिकायत सोमवार को की। आरोप है कि आश्रय केंद्र के संचालन से जुड़े कर्मचारियों ने लापरवाही के चलते बछडो.की मौत हुई इसमें समय से चारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे बछडो. की मौत हो गई। सोमवार को शिकायत पर मौके पर पहुंचे जिला पंचायत के कर्मचारियों ने केंद्र का निरीक्षण किया ।

प्रवक्ता के अनुसार जिला पंचायत की तरफ से जिले में कुंडौली, करचो, खुखुंदू और बैकुंठपुर में गो आश्रय केंद्र का संचालन किया जाता है। जिसमें लार ब्लॉक के भागलपुर-सलेमपुर मार्ग पर कुंडौली गो आश्रय केंद्र है। जिसमें 25 गोवंश को रखने की जगह है। विभागीय पोर्टल पर यहां 40 पशु दर्ज हैं ग्रामीणों का कहना था कि यहां 45 गोवंश रखे गए थे।

बताया जा रहा है कि शनिवार को चार, रविवार को छह और सोमवार को तीन बछड़ों की मौत हो गई। जब विभाग के कर्मचारियों को भनक लगी तो शनिवार को तीन, रविवार को छह और सोमवार को चार बछड़ों को गोशाला से ले जाकर गड्ढे में दफना दिया गया।

होगी कार्रवाई

इस संबंध में एसडीएम सलेमपुर क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि पशुओं के मौत की जानकारी है। केयर टेकर कहीं चला गया था। जिससे यह हालत हुई है। बीडीओ लार को आज मंगलवार को मौके पर भेजा गया है। गोवंश के लिए चारा-पानी नहीं मिलना कष्टदायक है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होगी।

शेयर मार्केट के नाम पर डिजिटल मायाजाल, ललितपुर पुलिस ने किया ध्वस्त

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। शेयर मार्केट में निवेश कर कई गुना मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का ललितपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने फर्जी नामक ऐप और वेबसाइट के जरिए शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पदार्फाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ब्रेजा और थार कार भी बरामद की हैं।

पुलिस की प्रारंभिक डिजिटल जांच में गिरोह के पास से करीब 6,357 संभावित पीड़ितों से संबंधित डेटा मिला है। इसके अलावा करीब 600 म्यूल बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी सामने आए हैं। इन खातों के माध्यम से ठगी की रकम को इधर-उधर किए जाने की आशंका है। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य आपस में मिलकर नाम से फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप संचालित करते थे। इसके जरिए लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने पर कई गुना लाभ मिलने का भरोसा दिलाया जाता था। गिरोह के सदस्य अलग-अलग नामों से खुद को एडवाइजर, हेड और असिस्टेंट एडवाइजर बताकर मोबाइल फोन व व्हाट्सऐप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते थे।

दिल्ली में शोर और शराब का विरोध करने पर मणिपुरी संगीतकार की पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के किलोकरी गांव में शोर-शराबे और कथित तौर पर शराब पीने का विरोध करना एक मणिपुरी संगीतकार को भारी पड़ गया। आरोप है कि घर के बाहर शोर कर रहे डिलीवरी कर्मियों और ढाबा कर्मचारियों से विवाद के बाद सी. विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल विक्रम को उनके बेटे याइफाबा ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस की शुरूआती जांच के मुताबिक, विक्रम सिंह अपने फ्लैट के बाहर हो रहे शोर-शराबे से परेशान थे। बताया जा रहा है कि वहां कुछ डिलीवरी कर्मी और ढाबा कर्मचारी मौजूद थे। आरोप है कि कुछ लोग वहां शराब भी पी रहे थे।

विक्रम ने कथित तौर पर तेज आवाज में हो रहे शोर और शराब पीने पर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार के मुताबिक, पुलिस को विक्रम से मारपीट की सूचना पर पीसीआर कॉल मिली थी। शुरूआती जांच में सामने आया है कि हमले में डिलीवरी कर्मियों और ढाबा कर्मचारियों की भूमिका थी।

मुक्कों और घूंसों से किया हमला

आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद हमलावरों ने विक्रम सिंह को मुक्कों और घूंसों से बुरी तरह पीटा। मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उनका बेटा याइफाबा उन्हें तत्काल होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचा। हालांकि, इलाज के दौरान विक्रम की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की।

सात आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग भी हिरासत में

सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भरत कुमार, प्रमोद, रमजान खान, दीपांशु, मोहन विश्वकर्मा, विजय और मन्नू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की उम्र 19 से 36 वर्ष के बीच है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अलग-अलग ढाबों और खाद्य स्टॉल पर काम करते हैं। पुलिस अब घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले- किसी दबाव में नहीं आएगी अदालत

डीए-डीआर के भुगतान से जुड़े आदेश पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत कानून के शासन और संविधान के प्रति अपनी शपथ के अनुरूप काम करेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट किसी भी तरह के दबाव या प्रभाव में नहीं आएगा और सभी मामलों में कानून के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर जानबूझकर अदालत की अवमानना करने और तीन अगस्त को जारी हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने तीन अगस्त के अपने आदेश में पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की लंबित किस्तें तथा बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए थे।

सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकताओं की ओर से पेश वकीलों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अदालत के निदेर्शों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही है।

दोनों पक्ष टिप्पणी न करें

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस मिश्रा ने दोनों पक्षों को मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पक्षकारों के पास कहने या करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अदालत कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका ने संविधान की शपथ ली है और वह अपनी शपथ को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी पक्ष की दलीलों से प्रभावित नहीं होगी।

सरकार पर विज्ञापन को लेकर आरोप

याचिकाकताओं के वकील ने अदालत में दावा किया कि सरकार को डीए-डीआर का बकाया चुकाने तक बड़े पैमाने पर प्रिंट और सामाजिक माध्यमों पर विज्ञापन देने से बचने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक सितंबर को पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित कराया। वकीलों ने आरोप लगाया कि एक सितंबर को प्रकाशित इन विज्ञापनों पर सरकार ने करीब 340 करोड़ रुपये खर्च किए। याचिकाकताओं ने अदालत से ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, जो तीन अगस्त के आदेश को विवादित बनाने या उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याचिकाकताओं ने कहा कि अदालत के आदेश पर सवाल उठाने या उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास है। मामले में पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा निर्मल सिंह धनोआ और अन्य के खिलाफ दायर कानूनी याचिका पर हाई कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोहराया कि वह किसी दबाव में आए बिना संविधान और कानून के अनुरूप ही मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

कीव और मॉस्को के बीच मध्यस्थता की नई बिसात

कीव। अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की हालिया कूटनीतिक शटल कूटनीति ने रूस-यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर एक नया और दिलचस्प अध्याय खोल दिया है। यह सिर्फ युद्ध रोकने की कवायद नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा, भू-राजनीतिक समीकरणों और सर्दियों की चुनौतियों से निपटने का एक बड़ा रणनीतिक खेल बन चुका है। इस पूरी बातचीत का सबसे अहम और नया एंगल पारंपरिक सैन्य मदद से हटकर ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जिस तरह अमेरिकी एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) और वायु रक्षा प्रणालियों पर जोर दिया है, उससे साफ है कि यूक्रेन इस बार सर्दियों को केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि आर्थिक और बुनियादी ढांचे के बचाव के रूप में लड़ रहा है।

जहां ममता खुद हार गईं, वहां किसे लड़ाएगी टीएमसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि, इस बार की चर्चा उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर है, जो अभी तक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से नहीं की गई है। यह वही महत्वपूर्ण सीट है जहां 2021 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था, जिससे यह उपचुनाव और भी दिलचस्प हो गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा

यह सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें अखिल गिरि का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। टीएमसी इस सीट पर अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की चुनावी हार का प्रतीक रही है। वहीं, भाजपा ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक, मेघनाद पाल के नाम की चर्चा है, जिन्हें सीएम अधिकारी का करीबी माना जाता है। भाजपा का दावा है कि पार्टी की ओर से जिसे भी नामित किया जाएगा, वह उम्मीदवार मतदाताओं के लिए स्वीकार्य होगा। दोनों ही प्रमुख दल रणनीति के तहत नामों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जिससे यह मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है। नंदीग्राम के साथ ही पश्चिम बंगाल की एक और सीट रेजीनगर में भी उपचुनाव होना है। यह सीट आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी। कबीर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता थे, जिन्होंने पार्टी से निकाले जाने के बाद एजेयूपी का गठन किया और 2021 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर सीट पर जीत हासिल की थी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट और असम के नगांव लोकसभा क्षेत्र में भी 6 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है।

बृजभूषण सिंह की बेटी शालिनी राजनीति में आने को तैयार

बुलंदशहर। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी में हैं। बुलंदशहर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचीं शालिनी सिंह ने राजनीति में आने की अपनी इच्छा स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज में पहचान किसी पार्टी या टिकट से नहीं, बल्कि नेतृत्व और जनता के लिए किए गए काम से बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहता है, तो वह निश्चित रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगी।

शालिनी सिंह ने बताया कि वह पिछले करीब 15 वर्षों से नोएडा में सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह किसी पार्टी अथवा विपक्ष को देखकर नहीं, बल्कि सही मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने यूजीसी समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की। शालिनी सिंह का ससुराल भी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। उनकी शादी बिहार के आरा से पूर्व सांसद अजीत सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के इकलौते बेटे विशाल सिंह से हुई है। वर्तमान में शालिनी परिवार के साथ नोएडा में रहती हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति से भी जुड़ी हुई हैं, और हाल ही में उन्होंने संघ की इसी शाखा का सर्वोच्च प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। शालिनी सिंह के पिता, मां और दोनों भाई पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। बृजभूषण शरण सिंह दशकों से राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और कैसरगंज से छह बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी मां और बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। वह 1996 में गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। परिवार की राजनीतिक सक्रियता अब अगली पीढ़ी तक भी पहुंच चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे राजनीति में हैं। बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और 2017 से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने 2024 में कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे।

अब मोजतबा का लंदन वाला घर यानी आलीशान पेंटहाउस बिकेगा

लंदन। लंदन के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे इलाकों में से एक, पैलेस ग्रीन में स्थित बेहद आलीशान पेंटहाउस अब बिक्री के लिए रखे गए हैं। इनमें से एक पेंटहाउस की प्रस्तावित कीमत लगभग 12 मिलियन पाउंड (लगभग 140 करोड़ रुपये) है। इसी इमारत में मौजूद एक अन्य पेंटहाउस को पहले 16.75 मिलियन पाउंड में खरीदा गया था। रिपोर्टों के अनुसार, ये दोनों अपार्टमेंट ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से जुड़े माने जा रहे हैं। हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड में इनके मालिक के तौर पर ईरानी बैंकर अली अंसारी का नाम दर्ज है। ये महंगी प्रॉपर्टीज ब्रिटिश राजधानी में इजरायली दूतावास के बेहद करीब, 3ए पैलेस ग्रीन में स्थित हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि इन संपत्तियों से इजरायली दूतावास के पिछले हिस्से का सीधा दृश्य दिखाई देता है, जो 50 मीटर से भी कम दूरी पर है।

उम्र को दी मात, 32 दिन में 1,000 किमी पैदल चलकर शिर्डी पहुंचे चेन्नई के 10 बुजुर्ग साईभक्त

शिर्डी। मन में साईबाबा के प्रति अटूट श्रद्धा, दर्शन की प्रबल इच्छा और संकल्प पूरा करने का जुनून हो तो उम्र भी भक्ति के रास्ते में बाधा नहीं बनती। चेन्नई के 10 वरिष्ठ साईभक्तों ने इसे सच साबित कर दिखाया है। इन श्रद्धालुओं ने करीब 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा 32 दिनों में पूरी कर शिर्डी पहुंचकर साईबाबा के दर्शन किए। साईबाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर ने संस्थान की ओर से सभी पदयात्रियों का स्वागत किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से इन श्रद्धालुओं ने शिर्डी के लिए पदयात्रा शुरू की थी। करीब एक हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उन्होंने प्रतिदिन औसतन 45 से 50 किलोमीटर पैदल यात्रा की। तेज धूप, बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद उनकी यात्रा लगातार जारी रही। पैरों में दर्द और रास्ते की मुश्किलों के बावजूद उनके कदम शिर्डी की ओर बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के होठों पर लगातार ह्यॐ

साई रामह्न का जाप और मन में साईबाबा के दर्शन की आस बनी रही। दिनभर की यात्रा पूरी करने के बाद कुछ समय आराम और फिर अगले दिन नए उत्साह के साथ पदयात्रा शुरू करना उनकी दिनचर्या रही।

11 साल से जारी है पदयात्रा

चेन्नई से शिर्डी की यह पदयात्रा पिछले 11 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। इस वर्ष इस परंपरा का 12वां साल था। खास बात यह है कि पदयात्रा में शामिल सभी 10 श्रद्धालु चेन्नई में सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी इन श्रद्धालुओं ने साईभक्ति का सिलसिला जारी रखा है। हर साल चेन्नई से शिर्डी तक पैदल आकर साईबाबा के दर्शन करने का उनका संकल्प अब एक परंपरा बन चुका है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा के दौरान साईचरित्र की सीख ह्यजया मनी जैसा भाव, तैसा अनुभवह्न का अनुभव उन्हें लगातार हुआ। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्हें महसूस होता रहा कि साईबाबा का आशीर्वाद उनके साथ है। इसी विश्वास ने उन्हें करीब एक हजार किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करने की शक्ति दी।

संस्थान की ओर से किया गया सम्मान

शिर्डी पहुंचने पर साईबाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर ने सभी पदयात्रियों का स्वागत किया। संस्थान की ओर से उन्हें शाल और उदी देकर सम्मानित किया गया। गाडीलकर ने प्रार्थना की कि श्रद्धालुओं की साईसेवा इसी तरह आगे भी जारी रहे और साईबाबा का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहे। इन बुजुर्ग साईभक्तों की पदयात्रा ने यह संदेश दिया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और अटूट श्रद्धा के सामने उम्र, दूरी और कठिन परिस्थितियां भी छोटी पड़ जाती हैं। 32 दिनों में 1,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर इन श्रद्धालुओं ने भक्ति और संकल्प की मिसाल पेश की है।

अभिजीत दीपके बोले- छात्रों और पत्रकारों को परेशान करने में व्यस्त दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने किलोकरी गांव में 54 वर्षीय मणिपुरी संगीतकार सी. विक्रम सिंह की कथित पीट-पीटकर हत्या का मामला उठाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र की कटिंग साझा की। इसमें दावा किया गया है कि सी. विक्रम सिंह अपने अपार्टमेंट के बाहर शराब पीने और शोर मचाने वाले कुछ लोगों का विरोध करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक समूह ने उन पर कथित तौर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह को उनके बेटे ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

समाचार कटिंग साझा करते हुए अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर छात्रों को परेशान करने और पत्रकारों के साथ कथित मारपीट में व्यस्त रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस वास्तविक अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय छात्रों और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि, अभिजीत के इन आरोपों पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब एक डिजिटल समाचार मंच से जुड़ी दो महिला पत्रकारों ने हाल ही में दिल्ली पुलिस पर कथित मारपीट के आरोप लगाए थे। पत्रकारों का दावा था कि उन्हें उनकी मुस्लिम पहचान के कारण निशाना बनाया गया।

पत्रकारों के मुताबिक, 3 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साकेत स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वे वीडियो बना रही थीं। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछताछ की। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि बाद में उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की।

दोनों पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कथित चोट के निशान भी दिखाए और दावा किया कि ये चोटें पुलिस की लाठी से लगी हैं।

हिंदू ग्रुप के कारण ड्यूटी से हटाई गईं महिलाएं

पेरिस। स्थित दुनिया के प्रतिष्ठित एफिल टावर के प्रवेश द्वार पर सोमवार को अप्रत्याशित रूप से ताला लग गया, जिससे इसे देखने आए हजारों पर्यटकों को निराशा का सामना करना पड़ा। इस बंद के पीछे एक हिंदू धार्मिक समूह की यात्रा को मुख्य वजह बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस धार्मिक समूह के दौरे से पहले टावर पर तैनात महिला कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से हटा देने का आदेश दिया गया था। इस निर्देश से वहां के कर्मचारियों में भारी गुस्सा फैल गया और उन्होंने सोमवार को ही हड़ताल का आह्वान कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एफिल टावर पूरे एक दिन के लिए बंद रहा।

दरअसल, एक हिंदू धार्मिक संगठन से जुड़े कुछ लोग एफिल टावर का दौरा करने वाले थे। इसी दौरान, कथित तौर पर टावर के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने महिला कर्मचारियों को उनकी सामान्य ड्यूटी से हटा दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि यह कार्यस्थल पर लिंग के आधार पर स्पष्ट भेदभाव का मामला है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह पुरुषों को तैनात कर दिया गया था। टावर का प्रबंधन करने वाली कंपनी इस पूरे मामले को लेकर सवालों के घेरे में है। कंपनी ने अपनी सफाई में कहा है कि हिंदू समूह ने यह अनुरोध किया था कि दौरे के दौरान महिलाओं के साथ बातचीत कम से कम की जाए। हालांकि, कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था।

इस घटनाक्रम के बाद, संबंधित हिंदू धार्मिक संगठन ने एक बयान जारी कर माफी मांगी है। संगठन ने कहा है कि यदि उनकी वजह से किसी को ठेस पहुंची है या कोई परेशानी हुई है तो उन्हें इसका गहरा खेद है। बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रतिनिधिमंडल में 100 से अधिक लोग शामिल थे और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पहले ही यह तय किया गया था कि किसी को परेशानी न हो। पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रबंधन कंपनी को इस तरह की शर्तें नहीं माननी चाहिए थीं। पेरिस शहर की शान, एफिल टावर, सीन नदी के किनारे स्थित 330 मीटर ऊंचा है।

हल्द्वानी मैदान के शुद्धिकरण मामले में हाई कोर्ट सख्त, बोला- पुलिस को जांच करने दें

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दर्ज प्राथमिकी और जारी जांच के बीच तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पर सवाल उठाया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और जांच से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा।

जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि जब प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है तो उसे अपनी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, एफआईआर दर्ज होने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए।

स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर हुई याचिका

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया था। आरोप है कि रैली के बाद कुछ लोगों ने मैदान में कथित रूप से शुद्धिकरण किया।

याचिका में घटना की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत

के सामने स्पष्ट किया कि याचिका का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है।

सरकार ने बताया- दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर

राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस की जांच जारी है। सरकार ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। याचिकाकर्ता की ओर से इस आरोप से इनकार किया गया। वकील ने कहा कि याचिका में केवल घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

सीसीटीवीऔरइलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश

सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण को महत्वपूर्ण माना। पीठ ने राज्य को मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर पुलिस की जांच को आगे बढ़ने देना ही उचित प्रक्रिया है। अदालत ने फिलहाल मामले में जांच जारी रहने के दौरान अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप से बचने का संकेत दिया।

जनता को बड़ी राहत : जमीन सीमांकन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर

रायपुर. राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है. अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (ष्टस्ष्ट/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे, जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है. आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे. राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी. राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (हृढ्ढष्ट) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट (श्व-ष्टश्वह्वह्ल) सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी. आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए. अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी.

प्रतिकात्मक तस्वीर

राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है. जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित क्क-1 और क्क-द्धढ्ढ नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की क्यूआर कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. जमीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है. ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि (छ्वद्ब1द्गह्म्ह्यद्बश्ठ) और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटल किया जा चुका है. राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है. राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

ताजा खबर
संक्षिप्त

छत्तीसगढ़ में पटवारियों के 200 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, जिलों में स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। पटवारी भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी। शासन के आदेश के अनुसार सबसे अधिक 15-15 पद सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में हैं।

सरगुजा के 439 ग्रापं में एक साथ मनारोजगार दिवस व आवास दिवस

रायपुर। सरगुजा की सभी 439 ग्राम पंचायतों में एक साथ मनाया गया रोजगार दिवस एवं आवास दिवस सरगुजा जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में एक साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार दिवस तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास दिवस में ग्रामीणों, श्रमिकों एवं आवास हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनके निराकरण की पहल की गई। रोजगार दिवस के दौरान ग्रामीणों एवं श्रमिकों को विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड, 125 दिवस रोजगार की गारंटी, रोजगार की मांग दर्ज कराने की प्रक्रिया, संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों तथा मजदूरी भुगतान से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से सरगुजा में बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना सरगुजा जिले में परिवारों को बिजली खर्च से राहत देने के साथ उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। घरों की छतों पर स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्र अब केवल घरेलू बिजली की जरूरत पूरी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हितग्राही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर विद्युत ग्रिड में भी योगदान दे रहे हैं। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत आमदरहा निवासी श्री आलम साय रजवाड़े इसकी प्रेरणादायी मिसाल हैं।

कॉंग्रेस पर साधा निशाना, बोले- भ्रष्टाचार करना कांग्रेस की संस्कृति

ओबीसी मोर्चा का संभाग स्तरीय सम्मेलन सीएम साय ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

रायपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रायपुर संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओबीसी समाज की भूमिका और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को ढाई साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओबीसी समाज की बड़ी आबादी का उल्लेख करते हुए समाज के योगदान और हुनर की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ओबीसी समाज अपने हुनर के जरिए बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नए भारत के निर्माण की दिशा में काम हुआ है और देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब देश में घुसकर मारने वाला देश बन गया है।

उन्होंने दावा किया कि भारत की मजबूत कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां बंद हो गई हैं।

नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को ढाई साल की सरकार का सबसे बड़ा काम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना है।सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के प्रयासों में सहयोग नहीं किया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार घोटाले होते रहे और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करना कांग्रेस की संस्कृति रही है।गौरतलब है कि इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा : बीजेपी के नेतृत्व में सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग

रायपुर । पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा की संभागीय बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू शामिल हुए। उन्होंने ओबीसी समाज की एकजुटता, सामाजिक सशक्तीकरण और संगठन की मजबूती पर विस्तार से अपने विचार रखे। तोखन साहू ने ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू एवं उनकी पूरी टीम को प्रदेश के कोने-कोने में जाकर ओबीसी समाज को जोड़ने, जागरूक करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की लगभग 67 जातियां आती हैं। हमारी जातियां भले अलग-अलग हों, लेकिन हमारी परंपराएं, रहन-सहन और सांस्कृतिक मूल्य एक है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें किसी छोटे दायरे में नहीं बंधना है, बल्कि अपनी एकजुटता को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। केंद्रीय राज्यमंत्री साहू ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि भारत की आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य ओबीसी समुदाय और तेली समाज से निकले बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है।

नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में तेजी लाएं : डिप्टी सीएम शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नवीन आपराधिक कानूनों के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों तथा अधिकारियों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक त्वरित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है तथा इसके लिए कानून में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जानी चाहिए। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (एनसीएलआई) डैशबोर्ड की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। डैशबोर्ड के प्रत्येक मापदंड की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की रैंकिंग में और सुधार के लिए हर स्तर पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई माह से राज्य की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी मापदंडों में सुधार की गति बनाए रखने के निर्देश दिए। कार्यात्मक दक्षता के मापदंड पर सुधार के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट सीधे न्यायालय तक पहुंचाने की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि विवेचना से लेकर विचारण तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो। इसी मापदंड के अंतर्गत उन्होंने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नाफिस) तथा ई-साक्ष्य के उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी थानों को तकनीकी एवं कार्यात्मक दृष्टि से शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि ई-समन जारी होने के बाद उसकी तामील शीघ्र सुनिश्चित की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर चार्जशीट ऑनलाइन माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए। गृह मंत्री श्री शर्मा ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचनाएं और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ-साथ मैदानी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, तभी नए कानूनों का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंच सकेगा।

किसानों को बड़ी सौगात : सात सिंचाई योजनाओं के लिए 30.74 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सात प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग नहरों के जीर्णोद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिलेवार स्वीकृत कार्यों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के बलौदा शाखा नहर (वितरक 11 एवं 12) में रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग एवं पक्के निर्माण कार्यों के लिए 4.99 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं, इससे 339.05 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इसी प्रकार सोंढूर परियोजना (बेन्द्री वितरक नहर) के भाटापारा शाखा नहर के बेन्द्री वितरक नहर की रिमॉडलिंग और सीसी लाइनिंग के लिए 4.82 करोड़ मंजूर। इससे 355 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा।

रायपुर जिला (धरसींवा विकासखंड) के भाटापारा शाखा नहर कार्य में महानदी परियोजना अंतर्गत विभिन्न सुधार कार्यों हेतु 4.20 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 14) के आर.डी. 2700 मीटर से 3500 मीटर तक नहर को ह्यूम पाइप के माध्यम से भूमिगत करने के लिए 4.90 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

मांढ़र ब्रांच केनाल सर्विस रोडरू आर.डी. 31600 मीटर से 32900 मीटर तक डामर रोड निर्माण के लिए 1.90 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 8 व माइनर 1) में भूमिगत पाइपलाइन तथा कंक्रीट और मुरमीकरण रोड निर्माण के लिए 4.92 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 11।, 13, 14 व माइनर्स) महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 4.97 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत इन विकास कार्यों से क्षेत्र में जल प्रबंधन बेहतर होगा और अंतिम छोर (टेल एरिया) तक किसानों के खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

केटीयूजेएम में राज्यपाल डेका ने एआई एंड मीडिया रिसर्च सेंटर का किया शुभारंभ, कन्या छात्रावास की भी दी सौगात

रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में अकादमिक गुणवत्ता, विकास और विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन पर जोर दिया. राज्यपाल ने एआई एवं मीडिया शोध केंद्र और नवपरिवर्तित सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ भी किया. साथ ही विश्वविद्यालय के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उनके साथ बिताए अनुभव और प्रेरणादायी प्रसंग साझा किए. राज्यपाल डेका ने कहा कि नारी शिक्षा, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए अनुकरणीय सावित्री बाई फुले की स्मृति में कन्या छात्रावास का नामकरण किया गया है. इस सुविधाओं से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल की छात्राओं को मीडिया शिक्षा में सहायता और सफलता मिलेगी. सूचना-संचार टेक्नॉलाजी क्रांति के दौर में मीडिया रिसर्च के क्षेत्र में आधुनिक प्रविधियों के उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए मधुकर खेर मल्टीमीडिया भवन में अवस्थित एआई और मीडिया रिसर्च केंद्र का मान. राज्यपाल के कर कमलों से शुभारंभ किया. सूचना प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र खण्डेलवाल ने राज्यपाल महोदय को एआई केंद्र की अकादमिक एवं शोध गतिविधियों की जानकारी दी. विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस सभा कक्ष में राज्यपाल का स्वागत करते हुए कुलपति प्रो डॉ मनोज दयाल ने कहा कि

विगत अकादमी सत्र की तुलना में इस वर्ष एडमिशन संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो मात्र एक संख्या नहीं लोगों का विश्वास है. कुलपति ने कहा कि हमने एक मंत्र पर काम किया है- ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट ट्रांजैक्शन अर्थात् न्यूनतम संसाधन में अधिकतम परिवर्तन. हमारी विश्वविद्यालय बहुत छोटी है, परन्तु हम लघुता में भव्यता के सूत्र पर कार्यरत हैं. हमारे तीन संकल्प हैं- हर छात्र हुनरमंद होगा, हर छात्र संस्कारयुक्त होगा और यहां कि हर गतिविधि में राष्ट्र प्रथम होगा. मीडिया विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद में राज्यपाल डेका ने कहा कि पत्रकारिता के छात्र होने के नाते सत्य को उद्?घाटित करने की जिम्मेदारी समाज ने आपके कंधों में सौंपी है. मीडिया शिक्षा में आपको पत्रकारिता को प्रभावित करने वाली शक्तियों, टीआरपी, विज्ञापन के दबाव सहित स्लीप ऑप टंग्स इत्यादि से होने वाली छोटी-बड़ी गलतियों पर ध्यान से अध्ययन करना चाहिए.

हरियाली क्वीन का ताज़ मधुमिता पाल और अम्बिका मिश्रा को

प्रेस क्लब में तीज महोत्सव तीज क्वीन बनी नेहा श्रीवास्तव

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीज महोत्सव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भावना बोरा और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा की मौजूदगी में तीजा महोत्सव के तहत रैंप वॉक, डांस, गायन एवं विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताओं सहित विविध आयोजन हुए। कार्यक्रम में महिला पत्रकारों एवं प्रेस क्लब की महिला सदस्यों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। महोत्सव में पारंपरिक तीजा उत्सव की संस्कृति और आधुनिक अंदाज का सुंदर समन्वय देखने को मिला। रैंप वॉक के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में अपनी प्रस्तुति दी, वहीं डांस और गायन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।

तीजा महोत्सव के इस आयोजन में तीज क्वीन का खिताब नेहा श्रीवास्तव को हरियाली क्वीन संयुक्त रूप से मधुमिता पाल एवं अंबिका मिश्रा को मिला वहीं फोटोजेनिक क्वीन - तजीन नाज कॉन्फिडेंस क्वीन - महिमा पांडे, चार्मिंग क्वीन - निक्की श्रीवास्तव, डांस क्वीन - अंकिता टाटिया, एलिगेंट क्वीन - रत्ना पांडे, फैशन क्वीन - श्वेता शर्मा, टैलेंट क्वीन - ज्योति सिंग, तीज पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर - शकुंतला तरार, बेस्ट हेयर स्टाइल - रुमा सेनगुप्ता, गेम्स स्पिरिट क्वीन - कमलेश्वरी साहू, बेस्ट ड्रेस्ड क्वीन - वर्षा यादव, बेस्ट स्माइल -तृषा अग्रवाल, बेस्ट मेकअप - डॉ. आकांक्षा दुबे, डांस में महिला प्रतिभाओं ने दी शानदार प्रस्तुति, डांस प्रतियोगिता में आकांक्षा दुबे, रिया साहू, अंकिता टाटिया, प्रज्ञा प्रसाद, रत्ना पांडे, किरण तिवारी, प्रगति अग्रवाल, नेहा श्रीवास्तव और वर्षा यादव ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। मधुमिता पाल ने पंडवानी प्रस्तुति के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की।

प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका

विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका पूर्व पत्रकार एवं भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे और समाजसेवी श्वेता पड्डा ने निभाई। प्रतिभागियों की प्रस्तुति, आत्मविश्वास, प्रतिभा, व्यक्तित्व और रचनात्मकता के विभिन्न पहलुओं का आकलन कर विजेताओं का चयन किया गया।

गायन में भी बिखरे सुर

गायन प्रतियोगिता में मंजूषा शर्मा, प्रीति निगम, श्वेता शर्मा, डॉ. आकांक्षा दुबे, अनुराधा गुप्ता और तजीन नाज ने अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

आयोजन में पदाधिकारियों और महिला सदस्यों की सक्रिय सहभागिता कार्यक्रम में रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित बड़ी संख्या में महिला पत्रकार सदस्य उपस्थित रहीं। तीजा महोत्सव के आयोजन और विभिन्न गतिविधियों के संचालन में अमृता शर्मा, प्रियंका कौशल, मीनल शर्मा, आकांक्षा दुबे, विनीता मंडल, सोनल भारद्वाज, सुजाता साहा और अंबिका मिश्रा ने सक्रिय भूमिका निभाई। रायपुर प्रेस क्लब के इस आयोजन ने महिला पत्रकारों एवं महिला सदस्यों को अपनी प्रतिभा, कला और व्यक्तित्व को मंच देने के साथ ही तीज पर्व की परंपरा, संस्कृति और उत्सवधर्मिता को जीवंत करने का अवसर प्रदान किया। महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी और विविध प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया।

गोल्डन टावर अमलीडीह में हर्षोल्लास से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनाने कल 8 सितंबर को दिल्ली में डीपीसी होने जा रही है। इसके लिए राज्य के चीफ सिकेट्री विकास शील और सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यवाहक सिकेट्री मुकेश बंसल कल सुबह दिल्ली जाएंगे। दरअसल, जीएडी सिकेट्री रजत कुमार अवकाश पर हैं। मुकेश उनके लिंक अफसर हैं। बता दें, पिछले साल हुई डीपीसी में 2013 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों को ही आईएएस अवार्ड हुआ था। सुमित अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और इस बैच में रिकार्ड 29 अफसर हैं। यानी तीन अफसरों के आईएएस बनने के बाद 26 अधिकारी अभी आईएएस के वेटिंग में हैं। हालांकि, इस बार भी सभी का नंबर नहीं लग पाएगा। पूरा बैच कंप्लीट होने में लगता है दो-तीन साल निकल जाएगा। इस साल राप्रसे से आईएएस बनने के लिए पांच पद खाली हैं। मगर डीपीसी तीन पद के लिए होगी। सौम्या चौरसिया के खिलाफ मामलों की वजह से उनका आईएएस प्रमोशन रुक गया था। यूपीएससी ने उनके नाम का लिफाफा बंद कर दिया था। जब तक उनका मामला क्लियर नहीं होगा, तब तक उनका लिफाफा बंद रहेगा। इसी तरह पीएससी घोटाले में गिरफ्तार हुई पूर्व एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक का भी लिफाफा बंद किया जाएगा।

सो, दो पद पाईपलाईन में रहेगा। तीन पद की ही डीपीसी होगी। कल यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में यूपीएससी में डीपीसी होगी। इस बैठक में डीओपीटी सिकेट्री या उनके प्रतिनिधि के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील और जीएडी के प्रभारी सचिव मुकेश बंसल मौजूद रहेंगे। चूकि 2013 बैच के उपर से तीन अफसरों को आईएएस अवार्ड हो चुका है। इसलिए अब चौथे, पांचवे और छठे नंबर के को आईएएस अवार्ड हो सकता है। 2013 बैच में चौथे नंबर पर अभिषेक अग्रवाल, पांचवे पर सचिन भुतड़ा और छठे पर राजीव पाण्डेय हैं। सब कुछ ओके रहा तो इन तीनों को आईएएस अवार्ड हो जाएगा। हालांकि,धूप और उमस के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम का बदलेगा मिजाज, मिलेगी राहत! आईएएस में अफसरों का सीआर महत्वपूर्ण होता है। मगर सरकार और चीफ सिकेट्री का रोल अहम होता है। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे राप्रसे अधिकारी आईएएस बन गए हैं, जो विभिन्न जांचों का सामना कर चुके हैं, या सस्पेंड हो चुके थे।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में वैभव सहित इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

नई दिल्ली। यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भारतीय टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतर रही इस भारतीय टीम में अधिकतर युवा खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीरीज में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और टीम में अपनी जगह मजबूत करने अवसर मिलेगा। इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन से इन युवाओं को भ्रविष्य के मुकाबलों के लिए जगह मिलेगी।

इस सीरीज में उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सहित इन युवा खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहेंगी। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के आधार पर इन खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए अवसर मिला है। कराने के बाद, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ भी मौका दिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने आखिरी टी20 मुकाबले में खेली गई 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने उनकी क्षमता का परिचय दिया था, और दलीप ट्रॉफी में भी उनका बल्ला खूब चला है। अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के सामने वैभव किस रणनीति से बल्लेबाजी करते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। उनकी युवा ऊर्जा और निडर अप्रोच टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है।

युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने न केवल विकेट चटकाए, बल्कि अपनी किफायती गेंदबाजी से भी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। घरेलू सरजमीं पर अफगानिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिश्नोई

अपनी गुगली और लेग ब्रेक से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम हैं। इस सीरीज में एक और दमदार प्रदर्शन करके वह भारत की टी20 टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे और विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे।

ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के पास भी इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने का बेहतरीन मौका होगा। हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में, नीतीश के पास खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वह चोट से उबरने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। उनकी बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी टीम को संतुलन प्रदान करती है। निचले क्रम में तेजी से रन बनाने और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाने की उनकी क्षमता टीम के लिए काफी मूल्यवान साबित हो सकती है।

मध्यक्रम के बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए यह सीरीज इस पार या उस पार वाली है। । इंग्लैंड के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में टीम में जगह नहीं दी गई थी। आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों में वह केवल 5 रन बना सके थे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ भी दो मुकाबलों में उनका कुल स्कोर 28 रन ही रहा। ऐसे में, संजू को इस सीरीज में अपने बल्ले से कमाल दिखाना होगा और चयनकताओं को यह साबित करना होगा कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा पर किसी को संदे नहीं है, लेकिन निरंतरता की कमी ने उनके करियर को प्रभावित किया है। इस सीरीज में एक बड़ी पारी उनके आत्मविश्वास को फिर से लौटा सकती है। इसके अलावा अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज से वापसी कर रहे हैं उनका खेलना हालांकि फिटनेस पर निर्भर करेगा।

भारत के खिलाफ मिली जीत ही पाक क्रिकेट की बदहाली का कारण बनी : मोहम्मद यूसुफ

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली से उसके पूर्व क्रिकेटर बेहद दुखी है। एक समय पाक टीम अपनी तूफानी गेंदबाजी के बल पर विश्व की सभी टीमों को कड़ी टक्कर देती थी पर आज उसे जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसी टीमें भी हरा रही हैं। पाक टीम के गिरते स्तर पर पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने भी निराशा जतायी है।

हैरानी की बात ये है कि यूसुफ ने इसके लिए 2021 टी20 विश्व कप में भारत पर मिली जीत को बताया है। यूसुफ के अनुसार उस मैच में मिली जीत से पाक खिलाड़ी लापरवाह और अतिआत्मविश्वास से घिर गये जिसके कारण ही टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया।

यूसुफ जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं। वह दुबई में खेला गया था, जहाँ पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। बाबर आजम ने नाबाद 68 रन और मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 79 रन बनाकर 152 रन का लक्ष्य बिना कोई विकेट खोये हासिल कर लिया था। यह जीत पाकिस्तान के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं थी क्योंकि उसे पहली बार आईसीसी विश्वकप में भारत के खिलाफ जीत मिली थी। इस पूर्व क्रिकेटर के अनुसार यहीं से पाक क्रिकेट का विघटन शुरू हो गया। यूसुफ ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि, भारत के खिलाफ 2021 में हमने जो मैच जीता था, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। क्योंकि उस जीत के बाद खिलाड़ियों को लगने लगा कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। वे यह नहीं समझ पाए कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छा प्रदर्शन करते समय भी खिलाड़ियों को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। यूसुफ ने चेतावनी दी कि यदि आप कॉलर उठाकर चलेंगे और विरोधी की इज्जत नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी और उनमें से बहुत सी समस्याएं पाकिस्तान क्रिकेट में आ चुकी हैं। उनका इशारा टीम के भीतर बढ़ते अहंकार और अनुशासनहीनता की ओर था।

यूसुफ ने टीम के भीतर की गुटबाजी पर भी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने खुलासा किया कि 2021 टी20 विश्व कप में जीत के बाद टीम में हर कोई पाकिस्तान टीम का कप्तान बनने की कोशिश कर रहा था, जिससे टीम को भारी नुकसान हुआ।

उन्होंने पिछले चार-पांच सालों में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन को रेखांकित किया, जिसमें एकदिवसीय विश्व कप, टी20 विश्व कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों में टीम लगातार हारी है। पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अथक प्रयासों की भी चर्चा की, जिसने टीम की मदद के लिए अनगिनत कोच बदले और रणनीतियाँ अपनाईं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी खिलाड़ी ने खड़े होकर जिम्मेदारी नहीं ली।

एकदिवसीय में सबसे अधिक रन देने का अनचाहा रिकार्ड है पाकिस्तानी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के नाम

लाहौर। एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रनों को देने का अनचाहा रिकार्ड पाकिस्तानी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के नाम है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंड शाहिद अफरीदी अपने आक्रामक बल्लेबाजी के साथ ही स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते है। अफ्ररीदी ने एकदिवसीय में जमकर रन बनाने के साथ ही विकेट भी लिए हैं पर उनकी गेंदों पर सबसे अधिक रन भी गये हैं। अफरीदी एकदिवसीय में एक मैच विजेता खिलाड़ी होने के साथ ही सबसे अधिक रन देने वाले गेंदबाजों में भी पहले नंबर पर हैं। साल 1996 से लेकर 2015 तक अपने 19 साल के लंबे एकदिवसीय करियर में अफरीदी ने 398 मुकाबलों की 372 पारियों में कुल 17,670 गेंदें फेंकी और 13,632 रन दिये। इन रनों के साथ ही उन्होंने 395 विकेट भी लिए। इसमें नौ

बार पांच या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि भी है। 4.62 की इकोनॉमी और 34.51 के औसत के साथ, ही अफरीदी पाक के एक मैच विजेता खिलाड़ी रहे हैं।

वहीं सबसे अधिक रनों के मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हैं। साल 1993 से 2011 के बीच 350 एकदिवसीयस खेलने वाले मुरलीधरन ने 341 पारियों में 18,811 गेंदें फेंककर कुल 12,326 रन दिये हैं। मुरलीधरन ने एकदिवसीय इतिहास में सबसे ज्यादा 534 विकेट हासिल किए हैं और वह टीम के सबसे बड़े मैच विजेता रहे हैं। इस दिग्गज का इकोनॉमी रेट सिर्फ 3.93 और औसत 23.08 का रहा, जो उनकी असाधारण क्षमता का प्रमाण है।

वहीं तीसरे पायदान पर भी श्रीलंका के ही पूर्व कप्तान और आक्रामक ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या हैं। साल 1989 से 2011 तक के अपने विशाल करियर में जयसूर्या ने 445 मुकाबले खेले। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर जयसूर्या ने लेफ्ट-आर्म स्पिन से भी टीम को मजबूती दी। 368 पारियों में 14,874 गेंदें फेंकते हुए उन्होंने 11,871 रन दिए, और इस दौरान 323 विकेट भी लिए। 4.78 की इकोनॉमी के साथ वह श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शुमार रहे।

वहीं चौथे स्थान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वसीम अकरम हैं। साल 1984 से 2003 तक 356 मैचों में अपनी रिवर्स स्विंग और गति का जादू बिखेरने वाले अकरम ने 351 पारियों में 18,186 गेंदें फेंकी। उन्होंने अपने करियर में 11,812 रन दिए पर 502 विकेट लेकर अपनी टीम को कई बार जीत दिलायी है।

इस सूची में पांचवें स्थान पर श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चमिंडा वास हैं। 1994 से 2008 के बीच 322 मैच खेलने वाले वास ने 320 पारियों में 15,775 गेंदें फेंकी और 11,014 रन खर्च किए। नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर वास ने अपने करियर में पूरे 400 विकेट हासिल किए। 4.18 की इकोनॉमी और 27.53 के औसत के साथ उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की कमान मजबूती से संभाली। वास के नाम वनडे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, 19 रन देकर 8 विकेट, भी दर्ज है।

मार्क कोल्स बने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच

हरारे। मार्क कोल्स जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच बने हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने कोल्स के नाम की घोषणा करते हुए उम्मीद जतायी कि वह टीम को आगे ले जाएंगी। इसे राज्य के क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरूआत भी बताया है। कोल्स की परीक्षा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज में होगी। यह दोनों देशों के बीच पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी।

मार्क कोल्स के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोचिंग का लंबा अनुभव है। वह पहले पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की महिला राष्ट्रीय टीमों के मुख्य कोच रहे हैं। उनकी यह भूमिकाएं उन्हें महिला क्रिकेट के गतिशील परिदृश्य और आवश्यकताओं की गहरी समझ प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्कॉटलैंड की पुरुष टीम को भी कोच के तौर पर सेवाएं दी थीं। वह क्रिकेट पापुआ न्यू गिनी में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर रहे है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न कोचिंग कंसल्टेंसी भूमिकाओं में भी

उनकी भूमिका रही है।

जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन तवेंगवा मुखुहलानी ने कोल्स की नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि, कोल्स के पास अंतरराष्ट्रीय कोचिंग और हाई-परफॉर्मेंस का काफी अनुभव है, साथ ही उन्हें महिला क्रिकेट की विशिष्ट जरूरतों की भी गहरी समझ है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोल्स, सीनियर और अंडर-19 ढांचे में नियुक्त तकनीकी और सहयोगी स्टाफ के साथ मिलकर, टीम को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। को ल्स के साथ काम करने के लिए, रंगारीराई मन्यांडे को असिस्टेंट कोच (बल्लेबाजी) और ट्रेवर फिरी को क्षेत्ररक्षक कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो टीम को हर मोर्चे पर सशक्त बनाने में सहयोग करेंगे।

कारोबार

शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 350 अंक टूटा; रियल्टी और आईटी पर दबाव

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार की शुरूआत मंगलवार को लाल निशान में हुई. सुबह 9:20 पर सेंसेक्स 332 अंक या 0.44 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 75,800 और निफ्टी 86 अंक या 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,692 पर था.

रियल्टी और आईटी शेयरों में भारी दबाव

शुरूआती कारोबार में बाजार में दबाव रियल्टी और आईटी शेयरों में देखा जा रहा था. सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी टॉप गेनर्स थे. इसके अलावा निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी पीएसयू बैंक भी लाल निशान में थे.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी कमजोर

दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसई और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हरे निशान

में थे. लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी कमजोरी देखी गई. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 31 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 20,067 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 98 अंक या 0.16 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 62,688 पर था.

सेंसेक्स पर इन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट

सेंसेक्स पैक में ट्रेंट, एमएंडएम, सन फार्मा, टीसीएस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एलएंडटी और एसबीआई लूजर्स थे. बीईएल, इटरनल, अदाणी पोर्ट्स और बजाज फिनसर्व गेनर्स थे.

एशियाई बाजार में दिखा मिला-जुला असर

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखा गया. टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि हांगकांग लाल निशान में था. अमेरिकी बाजार सोमवार को लेबर डे की छुट्टी के कारण बंद थे. जानकारों ने कहा कि बाजार में अब लगातार पांचवें हफ्ते से धीरे-धीरे लेकिन लगातार गिरावट देखी जा रही है. कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, आईटी शेयरों में बिकवाली, इस महीने फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका और तेजी से बढ़ते आईपीओ बाजार (जो काफी पैसा खींच रहा है) ने बाजार में इस धीमी गिरावट में योगदान दिया है. उन्होंने आगे कहा कि इस गिरावट की वजह बने मैक्रो-फैक्टर अभी भी मौजूद हैं. इस कारण मुमकिन है कि निकट भविष्य में भी यह गिरावट जारी रहे. लेकिन यह ट्रेंड लार्ज-कैप शेयरों में निवेशकों के लिए मौके भी बना रहा है, जो बेहतर फंडामेंटल के बावजूद कमजोर बने हुए हैं.

क्रूड में नए उबाल की आहट: 120 डॉलर पहुंच सकता है भाव

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर बड़े संकट की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ कच्चे तेल के निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस देशों ने अक्तूबर के लिए अपनी उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करते हुए आपूर्ति बढ़ाने पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया में जहाजों पर हमले और बढ़े, तो कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 96.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू बाजार एमसीएक्स पर कच्चे तेल की कीमत करीब एक फीसदी उछलकर सोमवार को 8,774 रुपये प्रति बैरल रही। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान सहित 7 प्रमुख सदस्य देशों की रविवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि नए उत्पादन कोटे तय होने तक उत्पादन नीति यथावत रखी जाएगी। अगस्त में ओपेक समूह ने सितंबर के लिए उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिससे 2023 में लागू की गई 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की चरणबद्ध वापसी पूरी हो चुकी है। हालांकि, जारी ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते जहाजों की आवाजाही में आ रही रुकावटों ने भौतिक तेल बाजार और कीमतों पर ओपेक देशों के प्रभाव को सीमित कर दिया है।

उधर, कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को छह सप्ताह के उच्च स्तर पर बनी रहीं। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.1% गिरकर 96.19 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। कारोबार के दौरान यह 97.93 डॉलर तक पहुंच गया। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, यदि पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में व्यापारिक जहाजों पर हमले और तेज होते हैं, तो कच्चा तेल उछलकर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। हालांकि, यदि क्षेत्रीय तेल निर्यात सामान्य बना रहता है, तो निवेश बैंक ने 80 डॉलर प्रति बैरल का निचला परिदृश्य भी आंका है। ग्लोबल कमोडिटीज रिसर्च विभाग के अनुसार, कच्चे तेल की तुलना में यूरोपीय गैस और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों में आपूर्ति व्यवधान का जोखिम कहीं अधिक है।

बैंक में नकद जमा करने वाले रखें ध्यान, पैसों का स्रोत न बता पाने पर लगेगा टैक्स व जुर्माना

नई दिल्ली। बैंक में नकदी जमा करने पर पैसों का स्रोत बताना अनिवार्य है। आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, स्रोत न बताने पर 84 फीसदी तक कर और जुमार्ना लग सकता है। करदाताओं को नकदी बिक्री के बीजक और बैंक अभिलेख सुरक्षित रखने चाहिए।

मौजूदा दौर में अगर कोई समझता है कि बैंक में नकद जमा करने के बाद सिर्फ कच्चे पर्चे देकर बचा जा सकता है, तो उसे आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल की पणजी बेंच का ताजा फैसला पढ़ना चाहिए। आभूषण निर्माण और सोने की बिक्री कारोबार से जुड़ीं सलमा महमादसलीम दफेदार ने नोटबंदी की घोषणा के दो दिन बाद 10 नवंबर 2016 को अपने बैंक खाते में एकमुश्त 32 लाख रुपये जमा किए। असेसिंग ऑफिसर ने पड़ताल के बाद करदाता के पास मौजूद 4.66

लाख के पुराने कैश बैलेंस, 6.51 लाख की सोने की बिक्री और 1.67 लाख की डिपॉजिट मैच्योरिटी को तो वैध माना, लेकिन बाकी बचे 19.15 लाख को अघोषित आय मान लिया।

आईटीएटी ट्रिब्यूनल का कड़ा रुख

3 सितंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में ट्रिब्यूनल ने कानूनी अंतर बहुत स्पष्ट कर दिया। करदाता ने 8.37 लाख रुपये की रकम को दुकान पर सोने की नकद बिक्री बताते हुए इसके समर्थन में कैश मेमो पेश किए थे। ट्रिब्यूनल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि इन कैश मेमो पर न तो ग्राहकों के नाम थे, न पते और न ही खरीदारों की कोई लिखित पुष्टि। ट्रिब्यूनल ने दो टूक कहा कि बिना ग्राहक की पहचान वाले अज्ञात पर्चे पैसे का वैध स्रोत साबित नहीं कर सकते। अंततः पुख्ता सबूतों के अभाव में करदाता को टैक्स चुकाना पड़ा।

करदाताओं के लिए जरूरी सबक

- नकद बिक्री पर इनवॉइस में ग्राहक का नाम, संपर्क व रजिस्टर में स्पष्ट आवक-जावक दर्ज रखें।
- पक्का बिल, पेमेंट वाउचर और शुद्धता का अधिकृत ब्योरा संभाल कर रखें।
- रिश्तेदारों से नकद लेते समय उनकी वित्तीय हैसियत व आईटीआर/बैंक रिकॉर्ड का प्रमाण पास रखें।
- पूर्व में निकाले गए कैश को दोबारा जमा करते समय यह तार्किक आधार होना चाहिए कि वह पैसा इतने दिनों तक घर में क्यों रखा रहा।

स्रोत साबित न होने पर कितना लगेगा टैक्स?

यदि बैंक में जमा नकदी स्रोत पेश नहीं किया जाता, तो असेसिंग ऑफिसर इसे धारा 68 (कैश क्रेडिट) या धारा 69ए (अघोषित नकदी) के तहत जोड़ देता है। इस पर धारा 115बीबीई के सख्त नियम लागू होते हैं:

अघोषित आय पर सीधे 60% टैक्स लगता है, जिस पर कोई बेसिक छूट सीमा नहीं मिलती।

टैक्स की रकम पर 25% सरचार्ज (कुल आय का 15%) और फिर 4% सेस जुड़ता है, जिससे कुल प्रभावी टैक्स देनदारी 78% हो जाती है।

यदि विभाग स्वयं जांच में यह गड़बड़ी पकड़ता है, तो धारा 271एएसी के तहत 10 फीसदी पेनल्टी लग सकती है। इस तरह कुल देनदारी लगभग 84 फीसदी तक पहुंच जाती है, जिसके ऊपर धारा 234ए/बी/सी का ब्याज अलग से लगता है।

इस रकम पर 80सी, 80डी जैसे कर दावों या कारोबारी नुकसान को समायोजित करने की अनुमति नहीं होती।

महत्वपूर्ण ख़बर

मध्यप्रदेश में पर्यटन-विकास का अध्ययन करने आएगा यूएई का दल

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में हुए पर्यटन विकास का अध्ययन करने शीघ्र ही यूएई का दल प्रदेश के दौरे पर आएगा। दुबई प्रवास के दौरान यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री श्री अब्दुल्लाह बिन तौक-अल- मार्री से भेंट के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूएई के मंत्री से भेंट के पश्चात जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में प्रति वर्ष पर्यटक संख्या बढ़ रही है। इसके लिए निवेशकों को होटल एवं होमस्टे प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हुई भेंट में यूएई के मंत्री ने जानकारी दी कि होटल एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश के लिए यूएई का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मध्यप्रदेश का दौरा करेगा। मध्यप्रदेश और यूएई के बीच हवाई सेवाओं के लिए भी यूएई पूर्ण सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूएई के पर्यटन मंत्री को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट :2027 में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।

संदिग्ध अवैध शराब की घटना पर जिला दंडाधिकारी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

- भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सागर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सागर जिले के बंडा क्षेत्र में संदिग्ध अमानक/अवैध शराब के सेवन से हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। विगत दिनों सागर जिले की शाहगढ़ तहसील के ग्राम नौराज एवं गूगारा खुर्द तथा बंडा तहसील के ग्राम बमूरा आदि में 4 एवं 5 सितंबर की दरम्यानी रात संदिग्ध अमानक/अवैध शराब के सेवन के बाद ग्रामीणों के बीमार होने तथा कुछ मरीजों की मृत्यु की घटना सामने आई थी। प्रभावित ग्रामीणों ने उल्टी, बेहोशी एवं शरीर में झटके जैसे लक्षणों की शिकायत के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बंडा पहुंचकर उपचार कराया।

मध्य प्रदेश के धार जिले में पहली बार दौड़ी ट्रेन, पीएम नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ

धार। धार जिले के लिए 8 सितंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले को पहली रेल सेवा की सौगात दी है। वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से धार जिले के 28 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित रेलखंड का लोकार्पण किया और यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पहली बार धार जिले के नक्शे पर रेल सेवा शुरू हो गई और जिले की धरती पर ट्रेन दौड़ती नजर आने लगी। धार में रेल सुविधा का सपना कई दशकों पुराना है। 8 फरवरी 2008 को झाबुआ में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना का शिलान्यास किया था।

टांडा रोड रेलवे स्टेशन पर इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर भी यहां पहुंची और टांडा रोड स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और स्वयं रामकोट तक रेल सफर करने बैठी।

रेल सेवा शुरू होने से सबसे बड़ा लाभ टांडा और आसपास के आदिवासी अंचल के लोगों को मिलने की उम्मीद है। खासकर रोजगार के लिए गुजरात और अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने वाले हजारों लोगों के लिए यह सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का नया माध्यम बनेगा। जिले के ऐसे भी अनेक लोग हैं, जिन्होंने अब तक ट्रेन देखी तक नहीं है या रेल में सफर नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं।

हालांकि धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के आगामी चरणों और इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के शेष कार्यों के पूरा होने का इंतजार अभी बाकी है। इसके बावजूद आज का दिन धार के लिए एक नए रेल युग की शुरूआत है।

धार की भोजशाला में सत्याग्रह के साथ मनाया रक्षाबंधन

बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र

धार। ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समाज की ओर से सत्याग्रह के तहत रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुख-समृद्धि की कामना की, वहीं भोजशाला की रक्षा और सनातन परंपराओं के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। आयोजन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

रक्षाबंधन के अवसर पर भोजशाला परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह नजर आया। बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ भोजशाला की रक्षा के संकल्प को भी इस पर्व से जोड़ा। उनका कहना था कि जिस तरह राखी भाई-बहन के रिश्ते में सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है, उसी तरह भोजशाला की रक्षा के लिए भी समाज को एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

हिंदू समाज की ओर से भोजशाला में नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे सत्याग्रह के तहत मंगलवार का आयोजन भी महत्वपूर्ण रहा। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ श्रद्धालुओं ने भोजशाला की रक्षा, धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़े विषयों को लेकर संकल्प लिया।

15 मई के बाद से लगातार आयोजन

गौरतलब है कि 15 मई के बाद से भोजशाला में हिंदू समाज की ओर से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। पूर्ण मंदिर का अधिकार मिलने के बाद समाज में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में अलग-अलग पर्व और धार्मिक अवसर भोजशाला परिसर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। मां की आराधना से लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजनों तक श्रद्धालुओं की भागीदारी देखने को मिल रही है।

मंगलवार को रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी इसी उत्साह की झलक दिखाई दी। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और साथ ही भोजशाला की रक्षा के लिए भी राखी बांधकर संकल्प दोहराया। आयोजन के माध्यम से समाज ने भोजशाला के प्रति अपनी आस्था और जुड़ाव को प्रदर्शित किया।

नकलचियों के मोबाइल हुए डिस्चार्ज

जांच के लिए इंदौर का डीएवीवी बनाएगा मोबाइल इन्वेस्टिगेशन कमेटी

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नकल प्रकरणों की जांच अब नई व्यवस्था के जरिए की जाएगी। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से जब्त किए गए मोबाइल महीनों तक बंद पड़े रहने से उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती हैं।

ऐसे में अनुचित संसाधनों की जांच समिति के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि मोबाइल में यह पता नहीं चल पाता कि विद्यार्थी ने परीक्षा के दौरान कितने प्रश्नों के उत्तर फोन देखकर लिखे थे। इससे नकल प्रकरणों पर उचित निर्णय लेने में देरी होती है। अब इस समस्या से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अलग से मोबाइल जांच समिति बनाएगा।

इंदौर में सिंगापुर टाउनशिप के रास्ते में बने अंडरपास में फिर

कार्यपरिषद ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय में सालभर स्नातक और स्नातकोत्तर की 780 से अधिक वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं। इनमें औसतन 250 से 300 नकल प्रकरण सामने आते हैं। कई मामलों में विद्यार्थियों के पास गाइड, पाठ्यपुस्तक या अन्य सामग्री के पन्ने मिलते हैं। इन पन्नों के आधार पर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि परीक्षा में किस तरह नकल की गई। इसलिए ऐसे मामलों में निर्णय लेना अपेक्षाकृत आसान होता है।

सबसे ज्यादा परेशानी मोबाइल से जुड़े मामलों में आती है। परीक्षा केंद्र से जब्त मोबाइल विश्वविद्यालय में जांच होने तक लंबे समय तक बंद रखे जाते हैं। इस दौरान बैटरी खत्म हो जाती है। मोबाइल चालू नहीं होने पर समिति यह देख नहीं पाती कि विद्यार्थी ने फोन में क्या देखा और उससे कितने सवालों के जवाब लिखे।

कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई ने बताया कि परीक्षा में मोबाइल लेकर आना ही नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद यदि प्रश्नपत्र हल करते समय किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल मिलता है तो उड़नदस्ता या केंद्राध्यक्ष नकल प्रकरण बनाता है। इसी को देखते हुए नई समिति बनाई जा रही है। नई समिति का काम सिर्फ जब्त मोबाइल की तुरंत जांच कर नकल से जुड़े तथ्य जुटाना होगा। इससे प्रकरणों की जांच में तेजी आएगी।

दिल्ली हादसे में मृत अक्षत का शव पहुंचा कटनी, इलाके में पसरा मातम

कटनी। दिल्ली साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे में जान गंवाने वाले कटनी के 19 वर्षीय छात्र अक्षत यादव का शव मंगलवार सुबह दुबे कॉलोनी निवास पहुंचा। शव लेकर जैसे ही एंबुलेंस घर के बाहर रुकी, स्वजनों की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

माता-पिता अपने इकलौते बेटे के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख पड़े। रिश्तेदार, पड़ोसी और बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर पहले से जमा थे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते रहे। पूरे इलाके में मातम पसरा रहा। अक्षत की असमय मौत से उसके स्कूल परिवार में भी गहरा शोक है।

डीएसपी स्कूल की प्रिंसिपल सीमा दुबे सहित शिक्षक और उसके साथी घर पहुंचे। प्रिंसिपल दुबे ने बताया कि अक्षत अक्सर उनसे कहता था कि वह यूपीएससी परीक्षा पास कर देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन हादसे ने उसके सभी सपनों को अधूरा छोड़ दिया।

अक्षत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वह सत्य निकेतन स्थित एक पीजी में रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। रात करीब डेढ़ बजे हादसे की सूचना मिलते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया। उस समय अक्षत के पिता राजस्थान गए थे और सूचना मिलते ही वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे।

अर्पित का पार्थिव शरीर पहुंचा देवास, परिजनों ने दी अंतिम विदाई

देवास। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को हुए इमारत हादसे में जान गंवाने वाले देवास के 18 वर्षीय छात्र अर्पित का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह देवास पहुंचा। कैलादेवी क्षेत्र स्थित जय बजरंग नगर में एंबुलेंस से शव उतरते ही माहौल गमगीन हो गया। बेटे का शव देखते ही मां और बहनें बिलख पड़ीं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अर्पित दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और सत्य निकेतन के एक पीजी में रहता था। परिजनों के अनुसार इमारत ढहने के बाद से ही उसका मोबाइल बंद हो गया था। अनहोनी की आशंका में माता पिता दिल्ली पहुंचे और घटनास्थल के साथ अस्पतालों में उसकी तलाश की। सोमवार सुबह मलबे से अर्पित का शव मिलने के बाद उसकी मौत की पुष्टि हुई। दिल्ली में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार सुबह शव देवास लाया गया। घर के इकलौते चिराग को खोने के सदमे में मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल था। अंतिम यात्रा शुरू हुई तो बहन भाई की अर्थी रोकने के लिए दौड़ पड़ी। रिश्तेदारों ने उसे संभाला। पिता भूपेंद्र ने जब युवा बेटे की अर्थी को कंधा दिया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

राजगढ़ में दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला

टीवी और बाइक की मांग पर पति समेत चार पर केस दर्ज

ब्यावरा। दहेज में टीवी और मोटरसाइकिल नहीं लाने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर ससुराल से भगा देने का मामला सामने आया है। ब्यावरा शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति सहित 4 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है।

हैसियत अनुसार दिया था दहेज का सामान

पुलिस के अनुसार फरियादिया डाली पति अरविन्द वर्मा उम्र 24 साल निवासी ग्राम ढकोरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी वर्ष 2024 में अरविन्द वर्मा पिता लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम करोंदी थाना पचोर से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। पिता ने हैसियत अनुसार दहेज का सामान भी दिया था। शादी के कुछ समय तक सब ठीक रहा, फिर पति अरविन्द, ससुर लक्ष्मीनारायण, सास कृष्णा बाई व जेठ अंकित वर्मा ने यह कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि तू अपने मायके से दहेज में टीवी और मोटरसाइकिल नहीं लाई। मोटरसाइकिल और टीवी लाएगी तभी रखेंगे।

प्रताड़ित कर घर से निकाला और दी धमकी

आरोपियों ने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता पिछले 6 महीने से अपने माता-पिता के घर ढकोरा में रह रही है। करीब 8 दिन पहले पति और ससुर ढकोरा आकर उसके पिता को धमका कर गए कि दहेज में बाइक-टीवी दोगे तभी लड़की को रखेंगे।

रिश्ता बिगड़ने के डर से उसने पहले रिपोर्ट नहीं की थी। अब पिता शिवचरण वर्मा व भाई गौरीशंकर वर्मा के साथ थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिलाओं को सितंबर में मिलेंगे 1500 रुपये

जानिए किस तारीख तक आएगी किस्त और पात्रता

भोपाल। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए संचालित लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त का इंतजार अब बढ़ गया है। डॉ मोहन यादव सरकार इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में 1500 रुपये प्रतिमाह ट्रांसफर किए जाते हैं।

सरकार सामान्य तौर पर हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच लाड़ली बहना योजना की किस्त जारी करती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी 15 सितंबर से पहले 40वीं किस्त की राशि महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच सकती है। इससे पहले रक्षाबंधन से पहले 19 अगस्त को सरकार ने योजना की 39वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान महिलाओं के खातों में 1500 रुपये की नियमित किस्त के साथ 250 रुपये गिफ्ट के रूप में भी ट्रांसफर किए गए थे।

लाड़ली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं को मिलता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में महिला की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह 60 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

जिस महिला या उसके परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वह पात्र नहीं होगी। परिवार में कोई आयकरदाता होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल या स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी या संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत सदस्य वाले परिवार भी अपात्र होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने वाले परिवार भी योजना के दायरे से बाहर हैं।

इसके अलावा, जो महिला किसी अन्य सरकारी योजना से प्रतिमाह 1250 रुपये या उससे अधिक प्राप्त कर रही है, वह पात्र नहीं होगी। वर्तमान या भूतपूर्व सांसद/विधायक के परिवार, चयनित या मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक अथवा सदस्य के परिवार भी अपात्र हैं। स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (पंच और उपसरपंच को छोड़कर) के परिवार, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले परिवार और ट्रैक्टर को छोड़कर चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार भी योजना का लाभ नहीं ले सकते।

हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी थीम पर 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा राष्ट्रीय पोषण माह

भोपाल। प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का आयोजन 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ह्यहमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारीह्ण थीम पर किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया बुधवार को 9वें राज्य स्तरीय पोषण माह का इंदौर से शुभारंभ करेंगी। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया बुधवार को इंदौर में एक माह तक चलने वाले इस अभियान में स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों, पर्याप्त प्रोटीन, आहार विविधता, बच्चों के पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर विशेष जोर रहेगा। जिला, परियोजना, सेक्टर और आंगनवाड़ी स्तर पर गतिविधियों का आयोजन कर अधिक से अधिक समुदाय को इससे जोड़ा जाएगा।

पोषण मेले में दिखेगी स्थानीय खाद्य विविधता

पोषण माह के दौरान पंचायत भवनों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों में पोषण मेले एवं रेसिपी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इनमें टेक होम राशन, गर्म पका भोजन, क्षेत्रीय पौष्टिक व्यंजन, स्थानीय दालें, चना, मूंगफली, सोया, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मिलेट्स और मौसमी सब्जियों से तैयार व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। अपने प्रोटीन को पहचानेंह्ण अभियान के माध्यम से परिवारों को प्रोटीन के विभिन्न स्थानीय स्त्रोतों और संतुलित आहार के महत्व की जानकारी दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्थानीय एवं विविधतापूर्ण ताजा नाश्ता और गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के साथ उसकी गुणवत्ता, मात्रा और स्वच्छता की निगरानी में मातृ सहयोगिनी समितियों, पंचायतों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर साप्ताहिक मेन्यू बोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे और समुदाय को उपलब्ध भोजन एवं निर्धारित मेन्यू की जानकारी दी जाएगी। पोषण माह के दौरान 11 सितंबर से शारीरिक माप दिवसों का आयोजन कर जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई/ऊंचाई सहित आवश्यक शारीरिक माप लेकर पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि की जाएगी।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।